हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 03 अंक - 11 बेमेतरा, सोमवार 24 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

मुख्यमंत्री साय ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की

रायपुर । पवित्र श्रावण मास में राजधानी रायपुर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर नजर आई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुढ़ियारी स्थित मारुति मंगलम परिसर में आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने भगवान शिव का विधि-विधान से रुद्राभिषेक एवं पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि, शांति, खुशहाली और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। उन्होंने कांवड़ यात्रा में शामिल शिवभक्तों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को पवित्र श्रावण मास की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति का विशेष अवसर है। इस पवित्र माह में कांवड़ यात्रा हमारी आस्था, भक्ति और समर्पण की अनुपम अभिव्यक्ति है। हजारों शिवभक्त पवित्र जल लेकर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए पैदल निकलते हैं।

कठिन यात्रा के बीच शिवभक्तों का उत्साह और श्रद्धा सनातन संस्कृति में निहित आस्था की शक्ति को प्रकट करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुढ़ियारी के मारुति मंगलम परिसर से हजारों कांवड़िए पवित्र जल लेकर महादेव घाट स्थित भगवान हटकेश्वरनाथ महादेव के जलाभिषेक के लिए रवाना हुए हैं। शिवभक्तों के जयघोष और भक्ति से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा है। यह आयोजन केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का उत्सव भी है। मुख्यमंत्री साय ने भगवान हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मंदिर छत्तीसगढ़ की प्राचीन शिव आराधना परंपरा का प्रमुख केंद्र है। महादेव घाट में विराजमान भगवान हटकेश्वरनाथ के प्रति प्रदेशवासियों की गहरी आस्था है। विशेष रूप से श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना करते हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान जितनी इसकी प्राकृतिक सुंदरता और लोक-संस्कृति से है, उतनी ही इसकी गहरी आध्यात्मिक परंपराओं से भी है। प्रदेश के अलग-अलग अंचलों में स्थित प्राचीन शिवधाम और शक्तिपीठ हमारी समृद्ध धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत के साहैं। यहां के पर्व, उत्सव और धार्मिक यात्राएं समाज को अपनी जड़ों और संस्कारों से जोड़े रखती हैं।

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आयोजनों में समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते हैं। इससे आपसी सद्भाव, सामाजिक एकता और समरसता की भावना मजबूत होती है। सेवा, सहयोग और सामूहिकता की यही भावना छत्तीसगढ़ की संस्कृति की विशेषता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों के विकास और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इससे हमारी आस्था के केंद्रों को नई पहचान मिलने के साथ धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को भी विस्तार मिल रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कांवड़ यात्रा में शामिल सभी शिवभक्तों को शुभकामनाएं देते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रदेश की निरंतर प्रगति की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि देवाधिदेव महादेव की कृपा छत्तीसगढ़ और प्रदेशवासियों पर सदैव बनी रहे। हर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आए तथा हमारा छत्तीसगढ़ विकास और जनकल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत, रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, महापौर मीनल चौबे, निगम-मंडलों के अध्यक्ष, गणमान्य नागरिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

मंत्री केदार कश्यप के काफिले में हादसा छह घायलों में से चार की हालत गंभीर

कोंडागांव जिले में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के काफिले में हुए सड़क हादसे में छह लोग घायल हो गए। घायलों में मंत्री के निजी सहायक (पीए), चालक और एक महिला पुलिसकर्मी समेत चार पुलिस जवान शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार चार घायलों को गंभीर स्थिति के चलते बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। हादसे के समय कश्यप अपने वाहन में मौजूद थे और बाल-बाल बच गए। कश्यप अपने गृह ग्राम फरसागुड़ा से कोंडागांव की ओर आ रहे थे। इसी दौरान जुनवानी के पास कोंडागांव से जगदलपुर की ओर जा रही एक स्कॉर्पियो अचानक मंत्री के काफिले के सामने आ गई और पहले मंत्री की कार से टकरा गई। इसके बाद स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर काफिले के अनुगामी वाहन से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि अनुगामी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार पुलिस जवान घायल हो गए। हादसे में मंत्री के निजी सहायक अनुराग शर्मा और चालक सुनील कुमार मौर्य को भी चोटें आईं। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल कोंडागांव जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर घायलों को रायपुर रेफर कर दिया गया। घायलों में मंत्री के निजी सहायक अनुराग शर्मा को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रायपुर रेफर किया गया है। चालक सुनील कुमार मौर्य के सिर, चेहरे और पैर में चोट आई है और उन्हें भी रायपुर रेफर किया गया है। प्रधान आरक्षक राजेश नेताम और आरक्षक सुगंतिन उसेंडी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और दोनों को रायपुर रेफर किया गया है। वहीं, आरक्षक त्रिलोतमा मदरू के सिर, सीने, पीठ और दाहिने हाथ में चोट आई है, जबकि आरक्षक नर्मदा मरकाम के सिर और बाएं कंधे में चोट लगी है। दुर्घटना में मंत्री के वाहन, अनुगामी वाहन और स्कॉर्पियो समेत तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में मंत्री केदार कश्यप को कोई गंभीर चोट नहीं आई है।

पीएम मोदी ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की तारीफ की, युवाओं से नई संभावनाओं को तलाशने को कहा

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं की तारीफ़ की और देश से बड़े सपने देखने, और ज़्यादा इनोवेशन करने तथा नई संभावनाओं को तलाशने का आग्रह किया।

मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफ ॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई! आइए, और बड़े सपने देखें, ज़्यादा इनोवेशन करें और नई सीमाओं को पार करें।

प्रधानमंत्री ने भारत के तेज़ी से बढ़ते अंतरिक्ष इकोसिस्टम को मज़बूत करने में युवा इंजीनियरों, डिज़ाइनरों, कोडर्स और वैज्ञानिकों की बढ़ती भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने निजी प्रतिभाओं के बढ़ते योगदान का भी ज़िक्र किया और कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की उपलब्धियाँ युवा भारतीयों की नई पीढ़ी को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

हाल के वर्षों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का काफ़ी विस्तार हुआ है। इसमें स्थापित अंतरिक्ष संस्थानों के काम के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, स्टार्टअप्स और तकनीकी इनोवेशन पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' अंतरिक्ष खोज में भारत की उपलब्धियों और विज्ञान व तकनीक में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। पीएम मोदी का संदेश वैज्ञानिक खोज और अंतरिक्ष अन्वेषण की भारत की भविष्य की यात्रा में योगदान देने के लिए युवा सोच को प्रोत्साहित करने पर सरकार के फ़ोकस को दर्शाता है।

एफपीआई ने अगस्त के पहले तीन सप्ताह में किया 20,802 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश

मुंबई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय पूंजी बाजार में अगस्त के पहले तीन सप्ताह में अबतक 20,802 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है। शुद्ध निवेश एफ्पीआई द्वारा बाजार में लगायी गयी राशि और बाजार से निकाली गयी राशि का अंतर होता है।

केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा के आंकड़ों के अनुसार, इस वृद्धि के पीछे मुख्य योगदान इक्विटी का रहा। अगस्त में इक्विटी और म्यूचुअल फंड में एफपीआई का निवेश बढ़ा है जबकि डेट और हाइब्रिड उपकरणों में उनका निवेश कम हुआ है। इक्विटी में एफ्पीआई का शुद्ध निवेश तीन सप्ताह में 23,544 करोड़ रुपये रहा। म्यूचुअल फंड में उनका निवेश 50 करोड़ रुपये बढ़ा। इस दौरान, डेट में एफपीआई 226 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की। हाइब्रिड उपकरणों से उन्होंने 2,566 करोड़ रुपये निकाले। यह लगातार तीसरा महीना है जब एफपीआई भारतीय पूंजी बाजार में शुद्ध रूप से लिवाल रहे हैं। जुलाई में उन्होंने 40,031 करोड़ रुपये और जून में 4,669 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था। इस साल अबतक एफपीआई ने 1,52,040 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है। इसमें अकेले इक्विटी से उन्होंने 2,30,529 करोड़ रुपये निकाले हैं।

रायपुर की ब्लू वाटर खदान में डूबे युवक का शव 77 घंटे बाद मिला

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव स्थित ब्लू वाटर खदान में डूबे आदिल खान (24) का शव करीब 77 घंटे बाद पानी की सतह पर मिला। आदिल की तलाश में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तीन दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थीं। शनिवार देर रात शव पानी की सतह पर आने के बाद उसे बरामद किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आदिल खान 19 अगस्त की शाम अपने तीन दोस्तों के साथ ब्लू वाटर खदान घूमने गया था। इस दौरान दोस्तों के बीच पानी के एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने की शर्त लगी। इसके बाद आदिल और उसका एक दोस्त पानी में उतरे। तैरने के दौरान आदिल धीरे-धीरे खदान के गहरे हिस्से में पहुंच गया और देखते ही देखते पानी में डूब गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था।

घटना की सूचना मिलने पर माना थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। बाद में एनडीआरएफ की टीम को भी सर्च ऑपरेशन में लगाया गया। ब्लू वाटर की अधिक गहराई और पानी के अंदर कम तापमान के कारण गोताखोरों को तलाशी अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लगातार तीन दिनों तक संभावित स्थानों पर खोजबीन के बावजूद आदिल का पता नहीं चल सका था। तलाशी अभियान लंबा खिंचने के कारण प्रशासन ने इंडियन नेवी से भी मदद मांगी थी। इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड की विशेष टीम रविवार को रायपुर पहुंचने वाली थी।

कनाडा बिना अमेरिका का राज्य बने उसके फायदे चाहता है

वाशिंगटन। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का '51वां राज्य' बनाने की अपनी मांग दोहराते हुए आरोप लगाया कि कनाडा बिना अमेरिकी राज्य बने उसके फायदे हासिल करना चाहता है। ट्रंप ने वार्ता विफल होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में 'ट्रूथ सोशल' पर लिखा, कनाडा एक राज्य होने के फायदे चाहता है, लेकिन राज्य बनना नहीं चाहता। उन्होंने कई वर्षों तक हमारे महान किसानों पर भारी शुल्क लगाए हैं। अब और नहीं। वार्ता टूटने के बाद अमेरिका ने कनाडा के कई उत्पादों पर 50 प्रतिशत नया शुल्क लागू कर दिया है। ट्रंप की यह टिप्पणी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता स्थगित किए जाने के बाद आई। कार्नी ने कहा था कि वाशिंगटन की ताजा मांगें आर्थिक रूप से अव्यावहारिक और अनुचित हैं तथा इनसे किसी भी संभावित समझौते के लाभ प्रभावित होते हैं। कार्नी ने कहा, उन्होंने बहुत ज्यादा मांगा और बहुत कम की पेशकश की। उन्होंने अमेरिकी कदमों को कनाडा पर हमला बताते हुए नए शुल्कों को गलत आकलन करार दिया और कहा कि इनका उद्देश्य हमें नुकसान पहुंचाना और बांटना है। अमेरिका ने 22 अगस्त से करीब 28 अरब डॉलर मूल्य के कनाडाई आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लागू किया है।

छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी

बिजली गिरने से बैगा दंपती की मौत, कन्हार नदी में युवक बहा

रायपुर । छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता के बीच रविवार को बारिश से जुड़ी दो अलग-अलग घटनाएं सामने आईं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बैगा दंपती की मौत हो गई, जबकि बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में कन्हार नदी पर बने एनीकट को पार करने के दौरान एक युवक तेज बहाव में बह गया। उसकी तलाश की जा रही है।

मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले सात दिनों तक बारिश की गतिविधियां बने रहने तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में रविवार सुबह करीब नौ बजे एक युवक कन्हर नदी में बने एनीकट को पार कर रहा था। इस दौरान एनीकट के ऊपर से पानी का तेज बहाव चल रहा था। युवक झारखंड के गोदरमाना से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा था, तभी वह पानी के बहाव की चपेट में आकर बह गया। घटना के बाद युवक की तलाश की जा रही है।

इधर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा ढपनीपानी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बैगा दंपती की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंगल सिंह अपनी पत्नी बिरस्पतिया बाई के साथ घर पर थे। तेज गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश के बीच उनके मकान पर बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों आंगन में बेहोश हो गए। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने 108 संजीवनी एक्सप्रेस की सहायता से मंगल सिंह और बिरस्पतिया बाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मरवाही पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले सात दिनों तक बारिश की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना है।

हाईकोर्ट के आदेश के पालन में देरी, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण से जुड़े एक प्रकरण में पूर्व में दिए गए आदेश का निर्धारित अवधि में पालन नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला गरियाबंद निवासी दायसिंह ध्रुव के स्थानांतरण से संबंधित है।

प्रकरण के अनुसार दायसिंह ध्रुव गरियाबंद के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में ड्राइवर के पद पर पदस्थ थे। गरियाबंद कलेक्टर ने उनका स्थानांतरण मैनपुर कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए ध्रुव ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका दायर की थी।

याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को सुप्रीम कोर्ट के एसके नौशाद रहमान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए न्याय दृष्टांत के आधार पर याचिकाकर्ता के प्रकरण का छह माह के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि निर्धारित छह माह की अवधि बीतने के बावजूद अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया गया और स्थानांतरण आदेश भी निरस्त नहीं हुआ।

इसके बाद दायसिंह ध्रुव ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू के माध्यम से उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका प्रस्तुत की। याचिका में कहा गया कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद स्वास्थ्य सचिव की ओर से निर्धारित समयसीमा के भीतर मामले का निराकरण नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के नियम 12(1) का उल्लेख करते हुए न्यायालय को बताया कि उच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालयों के आदेश की अवहेलना करने पर अवमाननाकर्ता अधिकारी को छह माह तक के कारावास तथा दो हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि अवमानना याचिकाओं की बढ़ती संख्या से न्यायालय का महत्वपूर्ण समय प्रभावित होता है और इसका असर अन्य मामलों की सुनवाई पर भी पड़ता है।

उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग, रायपुर के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से उनसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के कारण उनके विरुद्ध न्यायालय अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

कन्या आश्रम माध्यमिक शाला झाल में नवाचार की मिसाल, छात्राओं में रक्षाबंधन को लेकर जबरदस्त उत्साह

खुद के हाथों से राखी, भाइयों की कलाई पर सजेगा बहनों का प्यार,

बेमेतरा/मूक पत्रिका

बरमकेला। रक्षाबंधन का त्योहार केवल बाजार से खरीदी गई राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और भावनाओं का उत्सव है। इसी भावना को नई उड़ान देते हुए विकासखंड बरमकेला अंतर्गत कन्या आश्रम माध्यमिक शाला झाल में छात्राएं अपने भाइयों के लिए अपने हाथों से राखियां तैयार कर रही हैं।विद्यालय परिसर इन दिनों रंग-बिरंगे धागों, सजावटी सामग्रियों और छात्राओं की रचनात्मकता से गुलजार है। छात्राएं पूरे उत्साह के साथ राखी बनाने में जुटी हैं। कोई राखी को आकर्षक रूप दे रही है तो कोई उसमें अपनी भावनाओं का रंग भर रही है। खास बात यह है कि बाजार की तैयार राखी के बजाय बहनों के हाथों से बनी राखी अब भाइयों की कलाई पर सजेगी।

राखी में सिर्फ धागा नहीं, बहनों का प्यार भी- राखी बनाते समय छात्राओं के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। उन्हें बेसब्री से उस दिन का इंतजार है, जब वे अपने भाइयों की कलाई पर अपने हाथों से बनाई राखी बांधेंगी। छात्राओं के लिए यह गतिविधि महज एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते को महसूस करने और अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सामने लाने का अवसर भी बन गई है।

शिक्षकों की पहल ने दिया नवाचार को नया रंग -कन्या आश्रम झाल में इस अनूठी पहल को आगे बढ़ाने में शिक्षक सरोजनी साहू, खिरोद कुमार बरिहा, विजय साव, महावीर चौहान, संजय कुमार पंडा एवं हॉस्टल अधीक्षिका खिलेश्वरी नायक की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों और अधीक्षिका की पहल से छात्राओं को स्वयं राखी तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।यह पहल बच्चों को रचनात्मकता, आत्मनिर्भरता और अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ने का संदेश भी दे रही है।

बाजार की राखी नहीं, बहनों के हाथों का प्यार बनेगा पहचान -कन्या आश्रम झाल की यह पहल निश्चित रूप से उन स्कूलों के लिए प्रेरणादायक है, जहां त्योहारों को केवल कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय बच्चों को उससे जोड़कर सीखने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाता है।इस रक्षाबंधन पर जब इन छात्राओं के भाइयों की कलाई पर राखी सजेगी, तो उसमें सिर्फ रंग-बिरंगे धागे नहीं होंगे–उसमें बहनों की मेहनत, भावनाएं और भाई के प्रति अटूट प्रेम भी बंधा होगा।कन्या आश्रम झाल की बेटियों का संदेश साफहै–राखी खरीदी नहीं, दिल से बनाई जाती है और जब बहन के हाथों से बनती है, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है।

लापरवाही की मार : घरघोड़ा में फ्लाई ऐश से भरे जा रहे गड्ढे, बारिश के साथ खेतों में घुल रही राख

रायगढ़ /मूक पत्रिका

घरघोड़ा बाईपास क्षेत्र में गड्ढों और जमीन को समतल करने के लिए फ्लाई ऐश अनुचित तरीके से डाल जा रहे है। सामने आई तस्वीरों में सड़क किनारे बड़े पैमाने पर काली-भूरी फ्लाई ऐश जमा दिखाई दे रही है। वहीं, बारिश के बाद फ्लाई ऐश पानी के साथ बहकर आसपास के खेतों और जमीन की ओर फैलती जा रही है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि फ्लाई ऐश का उपयोग जमीन भराव या समतलीकरण के लिए किया जा रहा है, तो उसे उचित तरीके से ढकने, सीमांकन करने और बारिश के पानी के बहाव को रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कई स्थानों पर राख खुले में पड़ी है, जिससे बारिश के दौरान राख बहकर कृषि भूमि तक पहुंच रही है। फ्लाई ऐश के परिवहन और निपटान को लेकर रायगढ़ जिले में पहले भी सवाल उठते रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक दस्तावेज में रायगढ़ जिले में फ्लाई ऐश के अवैध अपवहन के मामलों में समतलीकरण के बाद मिट्टी की परत बिछाने जैसी कार्रवाई का उल्लेख है। वहीं, वर्ष 2026 में भी रायगढ़-घरघोड़ा क्षेत्र में फ्लाई ऐश के परिवहन और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर रिपोर्टें सामने आई हैं। अब घरघोड़ा बाईपास की तस्वीरों ने एक बार फिर फ्लाई ऐश के उचित निपटान और पर्यावरणीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय लोगों की मांग है कि संबंधित विभाग मौके का निरीक्षण कर यह जांच करे कि फ्लाई ऐश किस उद्देश्य से डाली गई है, इसकी अनुमति किस आधार पर है और खेतों में राख के बहाव को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

सुरक्षित भवः फाउंडेशन द्वारा सिलतरा में आयोजित रोड सेफ्टी क्लास में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश

रायपुर। सुरक्षित भवः फाउंडेशन द्वारा महेंद्रा स्पज एंड पावर लिमिटेड के सहयोग से 22 अगस्त 2026 को Phase-II, इंडस्ट्रियल एरिया , सिलतरा, रायपुर में रोड सेफ्टी क्लास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित यातायात व्यवहार को बढ़ावा देना रहा।कार्यक्रम का संचालन ,डिप्टी डायरेक्टर डॉ. निधि अग्रवाल द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा सड़क सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया।1.केशव राव डायरेक्टर सुरक्षित भवः फाउंडेशन उन्होंने संस्था के गठन एवं उद्देश्यों के बारे में बताया कि पिछले 14 वर्षों से सुरक्षित भवः फाउंडेशन निरंतर रोड सेफ्टी के क्षेत्र में कार्यरत है, संस्था को अवार्ड रिवॉर्ड के साथ 100 से अधिक विश्व प्रसिद्ध रिकॉर्ड प्राप्त है तथा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। 2. डॉक्टर संदीप धूपर अध्यक्ष सुरक्षित भवः फाउंडेशन उन्होंने भारत में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े एवं प्रतिवर्ष वाहन की बिक्री में हो रही बढ़ोतरी पर प्रकाश डाला , वीडियो के माध्यम से बताया कि अधिकांश दुर्घटनाएं तेज गति और लाइसेंस धारी चालकों के कारण होती है उन्होंने यह भी बताया कि दुर्घटना का शिकार अक्सर परिवार का कमाओ व्यक्ति होता है, जिससे परिवार को आर्थिक क्षति और देश को भी नुकसान होता है। 3. श्री मुनीश महाजन – डायरेक्टर, Mahendra Sponge and Power Ltd. श्री मुनीश महाजन ने सड़क सुरक्षा को संस्थागत जिम्मेदारी बताते हुए कर्मचारियों और वाहन चालकों में सुरक्षा की आदत विकसित करने पर जोर दिया।

टीईटी, पुरानी पेंशन और पदोन्नति की मांगः शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षा आयोग अध्यक्ष सुधीर गौतम को सौंपा ज्ञापन

2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता का किया विरोध

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। टीईटी की अनिवार्यता, पुरानी पेंशन और पदोन्नति समेत शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम को ज्ञापन सौंपा। बीजापुर के सामान्य दौरे पर पहुंचे आयोग अध्यक्ष से मोर्चा के पदाधिकारियों ने बीआरसी कार्यालय में मुलाकात की। जिला सह संचालक कैलाश रामटेके के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पहले उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत किया और फिर अपनी मांगें रखीं।

2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों का मुद्दा-मोर्चा ने ज्ञापन में कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून वर्ष 2010 में लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि कानून लागू होने की तारीख से ही उसका प्रभाव होना चाहिए। पूर्व की नियुक्तियों पर इसे लागू करने से लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के सामने भविष्य को लेकर चिंता की स्थिति बन रही है।

मोर्चा ने इस संबंध में संसद में अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन देने, सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर देने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग भी रखी गई।शिक्षकों की मांगों को आयोग अध्यक्ष ने ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने आगामी शिक्षा विभाग की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। शिक्षा आयोग शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े विषयों पर समय-समय पर सरकार को अपना अभिमत देता है।

शिक्षकों की प्रमुख मांगें

2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता को लेकर पुनर्विचार।

*प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ।

पदोन्नतिः सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर।*

शिक्षकों की वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग।

टीईटी से जुड़े प्रावधान में आवश्यक संशोधन की पहल।

ये रहे मौजूद

मोर्चा पदाधिकारियों में वसीम खान, विजय चापड़ी, पुरुषोत्तम चंद्रकार, अरुण सिंह, राजेश मिश्रा, राजेश यालम, प्रदीप साहनी, रमन झा और आशीष पाण्डेय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कानून-व्यवस्था की IG ने की समीक्षा, थाना प्रभारियों को दिए सख्त निर्देश..

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ में जिले के पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में जिले की कानून-व्यवस्था, अपराधों की रोकथाम और पुलिसिंग व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आम लोगों को बेहतर और संवेदनशील पुलिस सेवा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।बैठक में पुलिस महानिरीक्षक ने अपराधों की रोकथाम के साथ लंबित मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने थाना क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए थाना स्तर पर पुलिस की सक्रियता लगातार दिखाई देनी चाहिए।आईजी ने पुलिस विभाग में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न पोर्टल और ऑनलाइन सिस्टम को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी प्रविष्टियां समय पर, सही और अपडेट होनी चाहिए। थाना स्तर के कागजी रिकॉर्ड और ऑनलाइन रिकॉर्ड में किसी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। साथ ही पुलिसिंग में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया। बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आईजी के निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने, कानून-व्यवस्था पर लगातार नजर रखने, रिकॉर्ड और पुलिस पोर्टल की जानकारी अपडेट रखने तथा आम लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए।इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र कुमार पटेल, एसडीओपी बिलाईगढ़ दीपिका मिंज, एसडीओपी सारंगढ़ गोविंद दीवान, डीएसपी मुख्यालय संतोषी ग्रेस सहित जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे।

सेवा सुरक्षा को लेकर शिक्षकों ने रैली निकाल एस डी एम को ज्ञापन सौपा

आरंग(लखौली)। शिक्षक साझा मंच के आह्वान पर शनिवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता, सेवा सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन विसंगति एवं पूर्व सेवा की गणना सहित विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के 146 विकासखंडों में एक साथ रैली, धरना एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में विकासखंड आरंग में भी शिक्षकों ने रैली निकाल एस डी एम आफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।आंदोलन की खास बात यह रही कि शिक्षकों ने विद्यालय बंद किए बिना और विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित किए बिना अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। शिक्षक साझा मंच ने इसे आंदोलन की महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा कि शिक्षक अपने अधिकारों और सेवा सुरक्षा की लड़ाई लड़ने के साथ विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरह निभा रहे हैं।आरंग में बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में शिक्षक रैली में शामिल हुए। खराब मौसम के बावजूद शिक्षकों का उत्साह कम नहीं हुआ। रैली के दौरान टीईटी की अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों को सेवा सुरक्षा देने, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने तथा पूर्व सेवा की गणना सहित अन्य मांगों को लेकर नारे लगाए गए।शिक्षक साझा मंच के रविन्द्र राठौर ने कहा कि लंबे समय से शिक्षक सेवा सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अब शिक्षक संगठित होकर अपनी जायज मांगों को शासन के समक्ष रख रहे हैं। धरम दास पाटिल ने कहा कि यह आंदोलन व्यवस्था को बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे न्यायपूर्ण बनाने और शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है।मंच ने स्पष्ट किया कि सेवा सुरक्षा, वरिष्ठता एवं शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों के समाधान तक लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रहेगा।बैठक में महेंद्र कुमार साहू, संतोष चंद्राकर, समीर चंद्राकर, उपाध्यक्ष गिरजा शंकर देवांगन, गिरिजा शंकर अग्रवाल, सावित्री सोनकर, शीला मैडम, भागेश्वरी धर्मगुड़ी, ज्योति मैडम, नम्रता सोनी, रामनाथ साहू, रोमेश भारद्वाज, राजमोहन, इंद्रजीत वर्मा, अनिल कुमार चतुर्वेदी, घनश्याम धृतलहरे, डेमन डहरिया, तुका राम, नागेन्द्र देवांगन, साहू, श्रीवास्तव, छोटू राम साहू, विश्राम प्रसाद बंजारे, रामकुमार ध्रुव, उत्तम कुमार बंजारे, धीरेंद्र साहू, हुमन लाल साहू, चंद्रशेखर विश्वकर्मा, विमल चंद सोनवानी, करमचंद सोनवानी, अरुण कुमार पटेल, चन्द्रशेखर साहू, चरण वर्मा, ओमप्रकाश साहू एवं उदय राम साहू सहित शिक्षकगण उपस्थित रहे।

पहले 1100 पेड़ों की कटाई पर हुआ था विरोध, अब सामंजस्य के बाद परियोजना क्षेत्र में तेजी से हुई कटाई

नागरमुड़ा में अब 13 हजार पेड़ों की कटाई पूरी, ग्रामीणों के विरोध के बाद बदले हालात

रायगढ़/मूक पत्रिका

तमनार =क्षेत्र के नागरमुड़ा में प्रस्तावित जिंदल कोल ब्लॉक को लेकर पेड़ों की कटाई का मामला एक बार फिर चर्चा में है। कुछ समय पहले तक जहां परियोजना क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों के विरोध के चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी और कंपनी प्रबंधन को कटाई रोकनी पड़ी थी, वहीं अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों के साथ सामंजस्य बनने के बाद परियोजना क्षेत्र में कटाई का काम तेजी से आगे बढ़ा और जून-जुलाई तक करीब 13 हजार पेड़ों की कटाई पूरी किए जाने की जानकारी सामने आ रही है।गौरतलब हो कि नागरमुड़ा में प्रस्तावित कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था। शुरुआती चरण में करीब 1100 पेड़ों की कटाई के बाद ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया था। ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ वनाधिकार, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों से जुड़े सवाल उठाए थे। विरोध बढ़ने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने से स्थिति संवेदनशील हो गई थी।शुरुआती दौर में करीब 1100 पेड़ों की कटाई के बाद ग्रामीणों के विरोध ने जोर पकड़ा।

ग्रामीणों ने परियोजना क्षेत्र में आगे पेड़ों की कटाई रोकने की मांग की थी। विरोध के चलते कुछ समय के लिए कटाई का काम प्रभावित हुआ और कंपनी प्रबंधन को भी पीछे हटना पड़ा था। उस समय यह माना जा रहा था कि ग्रामीणों की आपत्तियों और वनाधिकार से जुड़े मुद्दों के निराकरण के बिना परियोजना की आगे की गतिविधियां आसान नहीं होंगी।नागरमुड़ा में कुछ समय पहले तक करीब 1100 पेड़ों की कटाई के बाद ग्रामीणों का विरोध परियोजना के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। इसके बाद कंपनी और ग्रामीणों के बीच बने सामंजस्य के साथ स्थिति बदली और कटाई का काम आगे बढ़ा। अब करीब 13 हजार पेड़ों की कटाई पूरी होने की जानकारी सामने आने के बाद परियोजना ने एक महत्वपूर्ण चरण पार कर लिया है।आपसी सामंजस्य से बनी बात इसके बाद कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच बातचीत और सामंजस्य की स्थिति बनने के साथ परिस्थितियां बदलती गई। कटाई का काम दोबारा आगे बढ़ा और अब सामने आई जानकारी के अनुसार जून और जुलाई माह तक करीब 13 हजार पेड़ों की कटाई पूरी हो चुकी है।शुरुआत में जहां 1100 पेड़ों की कटाई ही ग्रामीण विरोध का बड़ा कारण बन गई थी, वहीं बाद में यह संख्या कई गुना बढ़ गई। इससे यह स्पष्ट है कि शुरुआती विरोध के बाद परियोजना क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर परिस्थितियां काफी बदली हैं।

वन और पर्यावरण पर फिर उठे सवाल

हजारों पेड़ों की कटाई पूरी होने के बाद परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर सवाल भी फिर उठने लगे हैं। कोयला खनन परियोजना से प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय स्तर पर इसके प्रभाव को लेकर अलग-अलग तरह की चिंताएं सामने आती रही हैं।वहीं दूसरी ओर परियोजना समर्थक पक्ष की ओर से रोजगार, स्थानीय विकास और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की संभावनाओं को भी प्रमुखता दी जाती रही है। ऐसे में परियोजना को लेकर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। क्या कहते है विक्रांत कुमार रेंजर तमनार=नागरमुडा क्षेत्र में पहले 11 सौ पेड़ो की कटाई कर ली गई थी।जिसे विरोध के बाद बंद कर दिया गया था।ग्रामीणों से आपसी सहमति पर हुई बातचीत के बाद 13 हजार पेड़ो की कटाई पूरी कर ली गई है।

बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं एल्विश यादव, 'मालामाल वीकली 2' में आएंगे नजर

एल्विश यादव अब जल्द ही बॉलीवुड में बतौर एक्टर डेब्यू करने वाले हैं। यूट्यूबर से रियलिटी शो स्टार और अब बॉलीवुड एक्टर तक का उनका सफर काफी खास रहा है। एल्विश ने अपने एक्स अकाउंट पर फैंस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं, अपने फैंस के प्यार और सपोर्ट की वजह से हैं।

एल्विश ने फैंस के लिए लिखा खास मैसेज

एल्विश ने अपनी नई फिल्म का ऐलान करते हुए लिखा, 'नई फिल्म। नया सफर। मैं बाहर से आया हूं। बॉलीवुड में मेरा कोई नहीं था। आप लोगों के बीच से उठकर आया और आपके प्यार ने मुझे अब बड़े पर्दे तक पहुंचा दिया। आज जो कुछ भी हूं, आपके प्यार की वजह से हूं। और इसी प्यार की वजह से मैं 'मालामाल' हूं। बस प्यार बनाए रखना।'

इस फिल्म में नजर आएंगे एल्विश

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, एल्विश यादव फिल्म 'मालामाल वीकली 2' में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख, परेश रावल और राजपाल यादव भी दिखाई देंगे।

बता दें कि 'मालामाल वीकली' साल 2006 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को काफी सफलता मिली थी। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था। इसमें परेश रावल, ओम पुरी, रितेश देशमुख और अरबाज खान जैसे कलाकार नजर आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'मालामाल वीकली 2' में पहली फिल्म के तेश देशमुख, परेश रावल और राजपाल यादव वापसी कर रहे हैं। वहीं फिल्म में परिणीति चोपड़ा, रवीना टंडन और शिल्पा शिरोडकर को फीमेल कास्ट के तौर पर साइन किया गया है।

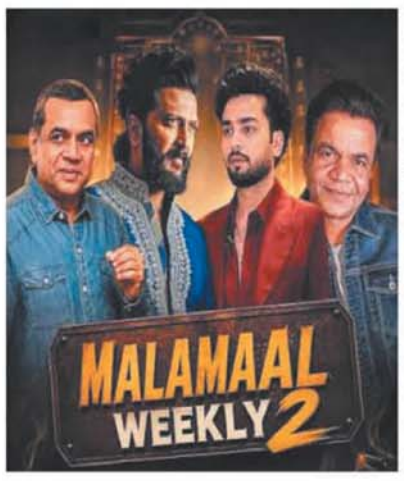

अंधभक्त कहे जाने से जुड़ा है मामला

कंगना रनौत ने ईशा कोप्पिकर को किया सपोर्ट

कंगना रनौत ने ईशा कोप्पिकर की वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट मंगलवार देर साझा की है। इस पोस्ट में वह भी खुद को 'भक्त' शब्द से संबोधित करती हैं। जानिए, कंगना ने अपनी पोस्ट में क्या-क्या लिखा है।

देश को लेकर कंगना ने कह दी बड़ी बात

कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ईशा कोप्पिकर की वीडियो साझा करती हैं और लिखती हैं, 'वाह, इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे हाई स्कूल में मैंने उस टीचर के खिलाफ आवाज उठाई थी जो असेंबली के दौरान बच्चों के सिर पर छड़ी से मारता था। मैंने 26/11 की हिंसा और निर्भया के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ भी आवाज उठाई। अपनी राह में आई किसी भी मुश्किल के लिए मैंने कभी अपने माता-पिता को दोष नहीं दिया। बल्कि मैंने अपने पूरे परिवार का जीवन-स्तर उतना ही ऊंचा उठाया, जितना मैंने खुद के लिए हासिल किया था।' कंगना आगे लिखती हैं, 'मैं जिससे भी मिलती हूं, लोग मुझे उनका 'भक्त' मान लेते हैं। जबकि मैं अपने देश और अपने लोगों से प्यार करती हूं।'

ईशा कोप्पिकर ने वीडियो में क्या कहा था?

सोशल मीडिया पर कुछ लोग ईशा कोप्पिकर को अंधभक्त बुला रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। इसके जवाब में उन्होंने एक वीडियो बनाया और उसमें कहा, 'हां मैं एक 'अंधभक्त' हूं। अगर अपने देश से प्यार करना और उसे तरक्की करते देखना ही भक्ति है, तो हां, मुझे भक्त या 'अंधभक्त' होने पर गर्व है।' ईशा आगे कहती हैं, 'मेरी यह अंधी भक्ति किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के लिए है। देश सबसे पहले। मैं सरकार से सवाल कर सकती हूं और उसकी नीतियों से असहमत भी हो सकती हूँ। और फिर भी पूरे दिल से अपने देश से प्यार कर सकती हूं।'

कंगना रनौत और ईशा करियर फ्रंट पर क्या कर रही हैं?

कंगना रनौत बतौर सांसद अपनी जिम्मेदार को निभा रही हैं। साथ ही वह एक्टिंग की दुनिया में भी सक्रिय हैं। इस साल वह फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आई। इसके अलावा वह फिल्म 'क्वीन 2' भी कर रही हैं। वहीं ईशा कोप्पिकर दो साल पहले एक तमिल फिल्म 'अयलान' में नजर आई थीं। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बात करती रहती हैं।

क्या शालिनी पासी ने पकड़ा मल्लिका शेरावत का झूठ?

मल्लिका शेरावत ने 'द ट्रेटर्स 2' में महिला प्रतियोगी को कहा कि उन्होंने नामी ब्रैंड डोल्से की ड्रेस पहनी है। जबकि शालिनी पासी को इस बात पर यकीन नहीं है। इस बात का सबूत भी उनके पास है। जानिए, मल्लिका सच्ची हैं या झूठीं?

मल्लिका का दावा क्या सच में झूठा निकला?

शो 'द ट्रेटर्स 2' की वायरल क्लिप में मल्लिका ने जब बताया कि उन्होंने नामी ब्रैंड डोल्से की ड्रेस पहनी है तो शालिनी ने दूसरे प्रतियोगी को जाकर सच्चाई बताई। वह कहती हैं, 'मैं उनका माइक ठीक करने गई और मैंने ब्रांड देखा। वह झूठ बोल रही हैं। मैं 17-18 साल की उम्र से ऐसी ड्रेस पहनती आ रही हूं। मेरी ड्रेस कस्टम-मेड होती हैं। मैं आपको तस्वीरें भेज सकती हूं। मैंने कई नामी ब्रैंड्स की ड्रेस भी पहनी है। यह वैसी नहीं है।' इस तरह शो में शालिनी पासी ने मल्लिका शेरावत का झूठ पकड़ लिया। हाल ही में शो 'द ट्रेटर्स 2' से मुनव्वर फारूकी, दिलीप ताहिल और करण सिंह मैजिक बाहर हुए हैं। जबकि अभी शो में आदित्य कुलश्रेष्ठ, अभिषेक मल्हान, अंश चोपड़ा, इक्का सिंह, क्रिस्टल डिसूजा, मल्लिका शेरावत, रिया चक्रवर्ती के अलावा कई सेलेब्स बचे हुए हैं।

क्या टीवी पर पहली बार नजर आएगी गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या की जोड़ी?

नया शो ला रहीं एकता कपूर!

गौरव खन्ना बीते कई दिनों से अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के तलाक वाले बयान के बाद से सुर्खियों में हैं। वहीं श्रद्धा आर्या भी टीवी के जाने-माने चेहरों में से एक हैं। अब खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों एकता कपूर के शो में नजर आ सकते हैं।

फैमिली ड्रामा का बन सकते हैं हिस्सा

खबरों के मुताबिक, दोनों एक्टर्स एकता कपूर के अपकमिंग रोमांटिक फैमिली ड्रामा का हिस्सा बन सकते हैं। यह शो स्टार प्लस पर आने की बात कही जा रही है। फिलहाल शो को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट और कास्टिंग स्टेज में है। अगर दोनों की कास्टिंग फाइनल होती है, तो यह पहली बार होगा जब गौरव और श्रद्धा किसी शो में साथ नजर आएंगे। टेली मसाला की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शो एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा होगा। कहानी में प्यार के साथ-साथ परिवार, रिश्ते और उनके बीच आने वाली परेशानियों को दिखाया जाएगा। इस शो को एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स तैयार कर रही है। फिलहाल मेकर्स शो के लिए बाकी कलाकारों की कास्टिंग पर भी काम कर रहे हैं।

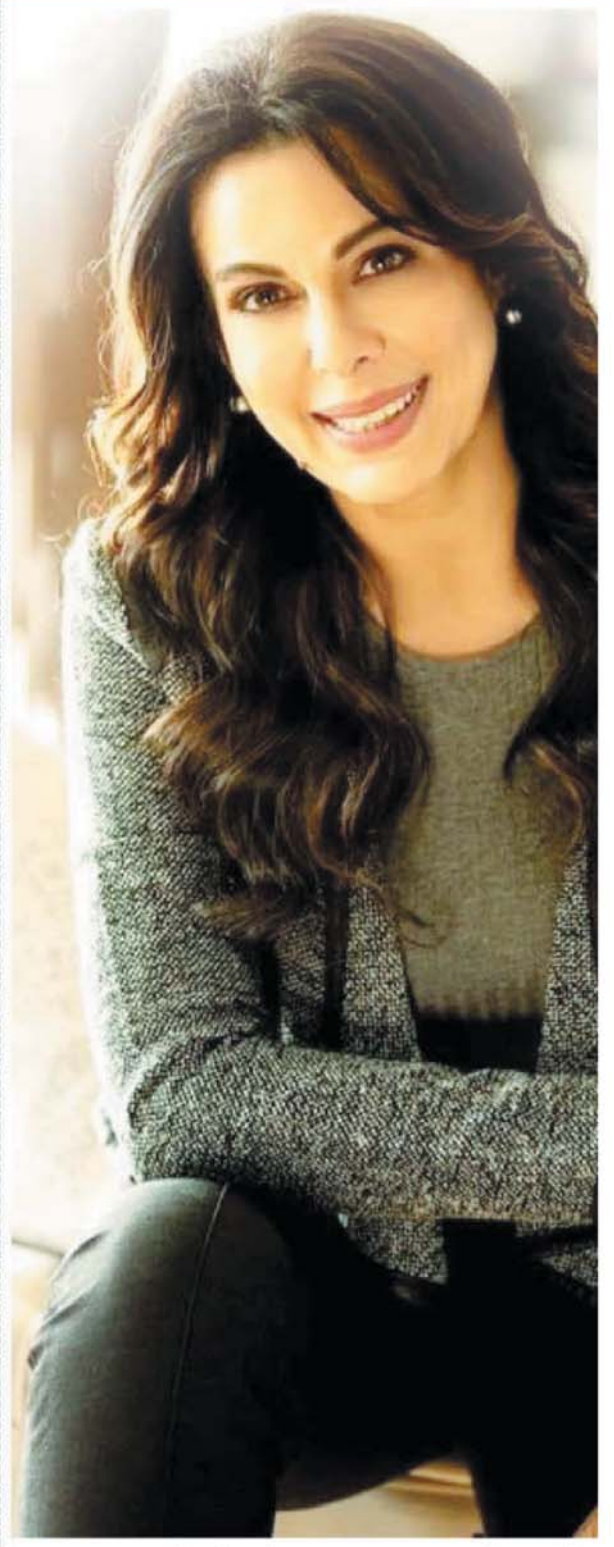

पूजा बेदी ने बताया क्यों नही करना चाहतीं शादी? सगाई और रिलेशनशिप को लेकर की बात

पूजा बेदी ने हाल ही में रिलेशनशिप को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने यह भी बताया कि शादी को लेकर उनकी सोच काफी बदल चुकी है। एक्ट्रेस ने अपने मंगेतर मानेक कॉन्ट्रैक्टर से शादी के बारे में भी काफी कुछ कहा।

पूजा बेदी ने विक्की लालवानी से बातचीत के दौरान शादी के इरादे पर बात की। उन्होंने कहा कि शादी उनके सपनों का हिस्सा नहीं है। वह खुद को शादीशुदा की तरह ही मानती हैं। पूजा बोलीं. कई साल बीत जाने पर शादी को लेकर मेरी सोच में काफी बदलाव आया है। मानेक कॉन्ट्रैक्टर से सगाई को 8 साल हो जाने पर भी शादी को लेकर अभी कोई प्लान नहीं है। मेरे लिए सगाई ही काफी है। शादी होना कोई जरुरी चीज नहीं है। ऐसा करने से कपल की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। वह अपनी-अपनी संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं। मैं आधिकारिक तौर पर शादी किए बिना भी खुद को शादीशुदा मानती हूं।

आर्थिक सुरक्षा पर क्या बोलीं पूजा?

आगे अपनी बातचीत में पूजा ने कहा, 'मेरी शादी हुई, मेरा तलाक हो गया, मेरे दो बच्चे हैं। उनकी भी शादी हुई, उनका तलाक हो गया, उनके भी बच्चे हैं। संपत्ति जैसी छोटी-छोटी बातों में तो सब कुछ बहुत सरल है। मेरी संपत्ति मेरे बच्चों को मिलेगी, उनकी संपत्ति भी उनके बच्चों को मिलेगी। मैं कमा रही हूं, वह कमा रहे हैं, हम दोनों आत्मनिर्भर हैं। मुझे सुरक्षा के लिए उनकी जरूरत नहीं है। उन्हें भी आर्थिक सुरक्षा के लिए मेरी जरूरत नहीं है।'

पूजा बेदी ने साल 1994 में व्यवसायी फरहान फर्नीचरवाला से पहली शादी की थी, जिनसे उनके दो बच्चे (अलाया और उमर) हैं। वर्ष 2003 में दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद फरवरी 2019 में उन्होंने मानेक कॉन्ट्रैक्टर से सगाई की है। बताते चलें पूजा बेदी ने 'जो जीता वही सिकंदर', 'लुटेरे', 'आतंक ही आतंक' और 'फिर तेरी कहानी याद आई' जैसी फिल्मों में काम किया है।

हम नफरत के खिलाफ खड़े हों, वही सच्ची देशभक्ति, धीमा सुनने वालों को धमाके की जरूरत

अपनी पहली हिंदी फिल्म 'रंग दे बसंती' हो या हालिया वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर', एक्टर सिद्धार्थ ने देशभक्ति वाली कहानियों और किरदारों में अलग ही छाप छोड़ी है। 'रंग दे बसंती' में शहीद भगत सिंह बने सिद्धार्थ इन दिनों 'ऑपरेशन सफेद सागर' में करगिल युद्ध में वीरगति पाने वाले स्क्वॉड्रन लीडर अजय आहूजा की भूमिका के लिए खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। इसकी एक वजह शायद यह है कि सिद्धार्थ निजी तौर पर भी खुद को हर मायने में देशभक्त मानते हैं।

अपनी देशभक्ति को लेकर वह कहते हैं, 'मैं तो बचपन से अपने को देशभक्त मानता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा सच बोला है। अगर मेरी आंखों के सामने कोई अन्याय हो रहा हो तो मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। मैं कभी टैक्स देने में झिझका नहीं हूं, तो मैं हर मायने में देशभक्त हूं। बाकी, मैं चाहता हूं कि आज हर तरफ जो नफरत की आग और आंधी फैल रही है, हम अगर उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो जाएं तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी देशभक्ति की मिसाल होगी। मैं बस यही कहूंगा कि प्यार बढ़ाओ यार।'

ऐसी जांबाजी सबके बस की बात नहीं

क्या ऐसे देशभक्ति वाले किरदार करते वक्त उनके भीतर भी ऐसा जज़्बा जोर मारता है? यह पूछने पर सिद्धार्थ कहते हैं, 'नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने देशभक्ति वाले रोल पहले भी किए हैं, लेकिन मुझे कभी एक सेकेंड के लिए भी यह नहीं लगा कि काश मैं खुद भी ऐसा कर पाता। इसलिए नहीं कि मैं वो बनना नहीं चाहता, बल्कि मुझमें वो बात ही नहीं है। यह जुनून, यह जज़्बा बहुत कम लोगों में होता है। अगर मुझे एनडीए जॉइन करना पड़ता तो पहले तो मैं चश्मा पहनता था, इसलिए एनडीए में जा नहीं सकता, लेकिन चश्मा ना पहनता तब भी मैं शायद नहीं जाता, क्योंकि मुझमें वह बात ही नहीं है। इसलिए, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं स्क्वॉड्रन लीडर अजय आहूजा बन गया हूं। मैं इस जन्म तो क्या, अगले जन्म में भी वैसा नहीं बन सकता। हम सिर्फ अदाकारी कर सकते हैं।'

हालांकि सिद्धार्थ इस भूमिका को निभाना एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। बकौल सिद्धार्थ, 'यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता होगा जब वो जिम्मेदारी का अहसास हमें न हुआ हो। अच्छी बात यह रही कि इसकी रिसर्च बहुत तगड़ी थी तो उससे आधा काम हो गया। बाकी, आधा काम उनके परिवार वालों का आशीर्वाद ने कर दिया तो हम उम्मीद है कि आज की नई पीढ़ी इस साहस के बारे में देख-सुनकर इससे प्रेरित हो।'

धीमा सुनने वालों को धमाके की जरूरत

सिद्धार्थ ने कहा कि यह कहानी नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी, मगर क्या उन्हें लगता है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में भी सिनेमाई कहानियां इतनी ताकतवर रह गई हैं कि लोगों की सोच बदल सकें? इस पर सिद्धार्थ कहते हैं, 'ये बहादुरी का किस्सा है और हमारी हजारों साल की परंपरा रही है कि हम बच्चों को कहानियां सुनाकर सुलाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं तो जब तक इंसान के बच्चे हैं, तब तक ऐसी कहानियां प्रासंगिक रहेंगी। इनकी बहुत जरूरत है और ये आनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया वाली बहुत जरूरी बात कही आपने। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कुछ पचास हजार लोगों में एक बंदा किताब पढ़ता था। आज साढ़े 5 लाख में एक बंदा किताब पढ़ता है। इंटरनेट पर सबकुछ है, लेकिन वहां पढ़ने-जानने की इच्छा किसी में नहीं है।'

संपादकीय

दागियों के भरोसे लोकतंत्र? मुकदमों के घेरे में 300 से ज्यादा सांसद

देश की राजनीति में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इस मुद्दे पर अलग-अलग समय में बहस और चर्चाएं भी होती रही हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में बताया गया कि देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ चार हजार से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।किसी भी समाज में यह उम्मीद की जाती है कि उनके जनप्रतिनिधि में उच्च स्तर की ईमानदारी, बेदाग छवि और दूरदर्शी सोच होनी चाहिए। एक आदर्श राजनेता उसे कहा जाता है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज के कल्याण को प्राथमिकता दे। मगर जब कोई नेता गंभीर आरोपों में घिरा हो, तो वह जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर कितना खरा उतर पाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में बताया गया कि देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ चार हजार से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें तीन सौ से ज्यादा सांसद तथा चौदह मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि राजनीति में शुचिता के मानदंडों पर क्या सही मायने में अमल हो पा रहा है? साथ ही इस पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि राजनेताओं के लिए विशेष व्यवस्था के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमे के निपटारे में इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है।

देश की राजनीति में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इस मुद्दे पर अलग-अलग समय में बहस और चर्चाएं भी होती रही हैं। इसके बावजूद विधायिका में ऐसे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति बनी हुई है, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सवाल सिर्फ मुकदमे जल्दी निपटाने का नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की मौजूदगी और जवाबदेही से भी है।इसमें दो राय नहीं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होना और उसका अपराध साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं। मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक उसे अदालत से दोषी न करार दिया जाए। मगर सवाल यह भी है कि जो समाज अपने नेता को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखता है, अगर वह गंभीर आरोपों में घिरा हो, तो उसे किस तरह देखा जाएगा?क्या इससे ईमानदार राजनीति की शुचिता प्रभावित नहीं होगी? नैतिकता का तकाजा तो यही है कि जब किसी जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगें, तो वह विधायी पद से खुद को अलग कर ले, लेकिन आज के समय में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं।

सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पर्यटक भारतीय सेना के जवानों के साथ बहस कर रही है और खुद को जेन जेड बताकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रही है। शायद इस महिला को पता नहीं कि सीमा पर खड़े सैनिक की ड्यूटी कोई पर्यटन सेवा नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे किसी पर्यटक की सुविधा, बहस या अधिकारों के नाम पर दरकिनार कर दिया जाए। साथ ही वीडियो में महिला खुद को जेन जेड बताते हुए यह कहती सुनाई देती है कि वह यह बकवास बर्दाश्त नहीं करेगी। यहां सवाल यह उठता है कि क्या किसी पीढ़ी का टैग राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल से ऊपर हो सकता है?

क्या जेन-जेड होना सुरक्षा नियम तोड़ने का लाइसेंस है? कारगिल में महिला पर्यटक के आचरण से उठे कई गंभीर सवाल

(नीरज कुमार दुबे)

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिखी घटना कारगिल सेक्टर के एक संवेदनशील हाई-एल्टीट्यूड चेक पोस्ट की है, जहां पर्यटकों के एक समूह को प्रतिबंधित दिशा में आगे बढ़ने से रोका गया। बताया जा रहा है कि संबंधित क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक अनुमति और सुरक्षा नियम लागू थे। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पर्यटक भारतीय सेना के जवानों के साथ बहस कर रही है और खुद को जेन जेड बताकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रही है। शायद इस महिला को पता नहीं कि सीमा पर खड़े सैनिक की ड्यूटी कोई पर्यटन सेवा नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे किसी पर्यटक की सुविधा, बहस या अधिकारों के नाम पर दरकिनार कर दिया जाए। साथ ही वीडियो में महिला खुद को जेन जेड बताते हुए यह कहती सुनाई देती है कि वह यह बकवास बर्दाश्त नहीं करेगी। यहां सवाल यह उठता है कि क्या किसी पीढ़ी का टैग राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल से ऊपर हो सकता है? बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिखी घटना कारगिल सेक्टर के एक संवेदनशील हाई-एल्टीट्यूड चेक पोस्ट की है, जहां पर्यटकों के एक समूह को प्रतिबंधित दिशा में आगे बढ़ने से रोका गया। बताया जा रहा है कि संबंधित क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक अनुमति और सुरक्षा नियम लागू थे। एक अन्य विवरण में इसे मिनामार्ग या मिनीमार्ग चेक पोस्ट के पास अस्थायी सड़क प्रतिबंध से जुड़ा बताया गया है। वीडियो में दिख रही तस्वीर बेहद स्पष्ट है। एक तरफ शांत रहकर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कराने की कोशिश करता जवान और दूसरी तरफ अपनी यात्रा, दूरी और अधिकारों का हवाला देकर बहस करता पर्यटक समूह। महिला पर्यटक का यह तर्क कि हम जेन जेड हैं, हम यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, दरअसल उस मानसिकता को उजागर करता है जिसमें व्यक्तिगत सुविधा को व्यवस्था और सुरक्षा से ऊपर मान लिया जाता है। जेन जेड होना न कोई विशेष सुरक्षा पास है, न ही यह कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल को चुनौती देने का लाइसेंस है। सेना यह नहीं देखती कि सामने खड़ा व्यक्ति किस पीढ़ी का है; उसे यह देखना होता है कि सीमा सुरक्षित रहे, कोई संदिग्ध गतिविधि न हो और कोई नागरिक अनजाने में किसी खतरे की जद में न पहुंच जाए। देखा जाये तो कारगिल और नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाके सामान्य पर्यटन स्थल नहीं हैं। यह वही संवेदनशील भूभाग है जहां भारत ने युद्ध का सामना किया है, जहां घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों का इतिहास रहा है और जहां मौसम, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां तथा सैन्य गतिविधियां हर समय सुरक्षा की अलग चुनौतियां पैदा करती हैं। ऐसे में सड़क बंद होना, आवाजाही नियंत्रित होना, चेकिंग होना या किसी क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति मांगना कोई एंटी-टूरिस्ट रवैया नहीं, बल्कि एक जरूरी सुरक्षा व्यवस्था है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों को वहां इसलिए तैनात रहना पड़ता है क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में खतरे केवल दिखाई देने वाले नहीं होते। कई बार खुफिया सूचना के आधार पर तलाशी या घेराबंदी की जरूरत पड़ सकती है। कभी सैन्य काफिले की आवाजाही होती है, कभी खराब मौसम या भूस्खलन के कारण रास्ता असुरक्षित हो जाता है और कभी किसी संभावित खतरे को देखते हुए नागरिकों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी जाती है। ऐसे निर्णय किसी एक पर्यटक को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि दर्जनों या सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए लिए जाते हैं। बर्फीली चोटियों, दुर्गम सड़कों और हर वक्त मौजूद संभावित खतरे के बीच जवान इसलिए तैनात है ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहें और पर्यटन जैसी सामान्य गतिविधियां भी संभव हो सकें। ऐसे में किसी पर्यटक का जवानों से यह पूछना कि रास्ता आखिर क्यों बंद किया गया है, हर परिस्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास मौजूद खुफिया जानकारी, किसी विशेष इनपुट या चल रहे ऑपरेशन का कारण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कई बार एक मामूली-सा खुलासा भी सुरक्षा अभियान और जवानों की जान को जोखिम में डाल सकता है। देश पुलवामा में सुरक्षा बलों के

काफिले पर हुए आतंकी हमले की भयावहता देख चुका है और पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले की त्रासदी भी झेल चुका है। ऐसे अनुभव साफ बताते हैं कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को लेकर एक छोटी-सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। इसलिए पर्यटकों को यह समझना होगा कि जब सेना या सुरक्षा बल किसी रास्ते को बंद करते हैं या आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो हर निर्णय के पीछे की वजह कैमरे के सामने बताना संभव नहीं होता।

ऐसे में जवान से बहस करना, वीडियो बनाकर उस पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाना या सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करना केवल असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीरता को न समझ पाने का उदाहरण है। सुरक्षा के मामले में सहयोग और धैर्य ही समझदारी है, क्योंकि कई बार जिस खतरे को आम नागरिक देख नहीं सकता, उसे रोकने के लिए ही जवान वहां खड़ा होता है। साथ ही वायरल हो रहे वीडियो में पर्यटक समूह के कुछ सदस्य यह कहते भी दिखाई देते हैं कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर से वहां पहुंचे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समझना होगा कि लंबी यात्रा किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश का अधिकारपत्र नहीं बन जाती। यदि किसी क्षेत्र के लिए परमिट जरूरी है तो पहले उसकी जानकारी लेना और नियमों का पालन करना पर्यटक की जिम्मेदारी है। विशेष रूप से लद्दाख और अन्य संरक्षित सीमावर्ती क्षेत्रों में नियम परिस्थितियों और सुरक्षा स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। सैन्य प्रतिष्ठानों, चेक पोस्टों और रणनीतिक स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी प्रतिबंधित हो सकती है। इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू वह भाषा और रवैया है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश दिखाई देती है। लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन संवेदनशील सैन्य चौकी पर ऑपरेशन या सुरक्षा प्रतिबंध के दौरान बहस करके आदेश बदलवाने का अधिकार किसी को नहीं है। संसद, टैक्स या किसी पीढ़ी का नाम लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को चुनौती देना न तो लोकतंत्र को मजबूत करता है और न ही नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली जोकि स्वाभाविक है। लोगों ने महिला पर्यटक और उसके साथियों के रवैये को अहंकारी और गैर-जिम्मेदाराना बताया है। जेन जेड वाली टिप्पणी पर मीम्स भी बन रहे हैं, लेकिन इस घटना को केवल मनोरंजन के रूप में देखने की बजाय इससे एक गंभीर सबक लेने की जरूरत है। कैमरे के सामने हंगामा करके वायरल होना आसान है, लेकिन सीमा की सुरक्षा में एक छोटी-सी चूक की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा वहां तैनात जवान को हमसे कहीं बेहतर है। यह चेतावनी केवल उस महिला पर्यटक के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया की लोकप्रियता, व्यक्तिगत सुविधा या पीढ़ीगत पहचान के नाम पर सुरक्षा नियमों को हल्के में लेते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा किसी हैशटैग, नारे या वायरल वीडियो के हिसाब से नहीं चल सकती। सीमा पर तैनात सैनिक को अपना काम करने दीजिए।

जनगणना में सिर्फ आबादी नहीं, बदलती जलवायु का हिसाब भी जरूरी

(कुशाग्र राजेंद्र)

आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। देश एक बार फिर जनगणना की तैयारी में है। लंबे अंतराल के बाद होने वाली यह जनगणना स्वाभाविक रूप से अनेक प्रश्नों के केंद्र में है। क्या इसमें जातिगत गणना होगी? इससे कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्यों को संसाधनों का बंटवारा किस आधार पर होगा? ये सभी सवाल महत्त्वपूर्ण हैं और लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा भी, लेकिन इनके बीच एक बुनियादी सवाल लगभग अनुपस्थित है और यह कि क्या इक्कीसवीं सदी की जनगणना उन वास्तविकताओं को दर्ज करने के लिए तैयार है, जिनका सामना आज का भारत कर रहा है?जनगणना प्रायः केवल आबादी गिनने की प्रक्रिया मानी जाती है। जबकि यह किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक दृष्टि का दर्पण होती है। कोई भी सरकार जिन बातों को जानना आवश्यक समझती है, वही उसके प्रश्नों में दिखाई देती हैं। इसलिए जनगणना केवल यह नहीं बताती कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि यह भी बताती है कि राज्य अपने समाज को किस नजर से देख रहा है और भविष्य की चुनौतियों को किस प्रकार समझना चाहता है। स्वतंत्र भारत की जनगणना समय के साथ बदलती रही है। आवास, पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई ईंधन, बैंकिंग सुविधा, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी जानकारियां इनमें क्रमशः जुड़ती गईं। इनसे शासन को विकास योजनाएं बनाने, सामाजिक असमानताओं को समझने और कल्याणकारी कार्यक्रमों को लक्षित करने में बड़ी सहायता मिली। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक भारत के निर्माण में जनगणना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। उत्तर भारत में तीव्र हो रही लू, भीषण गर्मी, पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती घटनाएं, असम और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़, बुंदेलखंड और दक्षिण में गहराता जल संकट, हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमनद झीलों के फटने का खतरा तथा पश्चिमी भारत में भूजल का लगातार गिरता स्तर, ये सभी घटनाएं अब अलग-अलग पर्यावरणीय समस्याएं नहीं रहीं। इनका सीधा असर खेती, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। विडंबना यह है कि इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमारे पास अलग-अलग विभागों में बहुत-सी सूचनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वे एक-दूसरे से जुड़ती नहीं हैं। मौसम का आंकड़ा एक संस्था के पास है, भूजल का दूसरे के पास, कृषि का तीसरे के पास और जनसंख्या का चौथे के पास। परिणाम यह है कि हमें यह तो पता है कि किसी गांव में कितने परिवार रहते हैं, लेकिन यह व्यवस्थित रूप से नहीं पता कि सूखते तालाब, घटता भूजल, बदलती फसलें या बार-बार आने वाली आपदाएं वहां के लोगों के जीवन और आजीविका को किस प्रकार बदल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में समस्या केवल आंकड़ों की कमी नहीं है। समस्या यह है कि हमारे पास जीवन और पर्यावरण को एक साथ देखने वाली सूचना व्यवस्था नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के प्रशासनिक इतिहास में ऐसी समग्र दृष्टि के उदाहरण पहले से मौजूद हैं। इसका एक उदाहरण 1887 में तत्कालीन मारवाड़ राज्य में जनगणना के लिए तैयार की गई ग्राम प्रश्नावली है। यह केवल गांव की आबादी या राजस्व का ब्योरा भर नहीं मांगती थी। इसमें कुओं और तालाबों की संख्या, पानी की गुणवत्ता, मिट्टी का प्रकार, चरागाह, वृक्षों की प्रजातियां, पशुधन, स्थानीय फसलें, कुटीर उद्योग, महामारी, अकाल, पलायन, स्थानीय धरोहर और गांव की सामाजिक संस्थाओं तक का विवरण दर्ज करने के 56 प्रश्न थे। गांव को केवल घरों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य, प्रकृति और स्थानीय संस्थाओं से मिलकर बने एक जीवंत तंत्र के रूप में देखा गया था। उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में तैयार अनेक जिला गजेटियर और ग्राम अभिलेखों में वर्षा, नदियां, जंगल, मिट्टी, सिंचाई, पशुधन, स्थानीय उद्योग तथा प्राकृतिक संसाधनों यहां तक कि रीति-रिवाज, खान-पान तक का विवरण जनसंख्या संबंधी सूचनाओं के साथ मिलता है। निस्संदेह इन दस्तावेजों का उद्देश्य औपनिवेशिक प्रशासन, राजस्व निर्धारण और अकाल प्रबंधन था, पर्यावरण संरक्षण नहीं। फिर भी उन्होंने गांवों का ऐसा सामाजिक-पर्यावरणीय चित्र सुरक्षित कर दिया, जो आज जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मूल्यवान स्रोत बन गया है।

'वंदे मातरम्' के अपमान से कांग्रेस के तुष्टिकरण की पोल खुली, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक एक ही पैटर्न?

'वंदे मातरम्' के हाल ही में किए गए अपराध और अपमान के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता और आधिकारिक व्यक्तव्य जो कह रहे हैं उसमें वे गांधी जी, नेताजी सुभाषचंद्र, गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर आदि का नाम लेते हुए इस गीत के विभाजन को उनकी से हुआ बता रहे हैं। यह एक भ्रमजाल और झूठ का पहाड़ है। गांधी जी तो इस बात के पक्षधर थे कि यह गीत संपूर्ण देश को जोड़ने वाला प्राणतत्त्व है और इसे इसके पूर्ण वैभव के साथ संपूर्णतः स्वीकार किया जाना चाहिए।

(प्रवीण गुगनानी)

'वंदे मातरम्' के हाल ही में किए गए अपराध और अपमान के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता और आधिकारिक व्यक्तव्य जो कह रहे हैं उसमें वे गांधी जी, नेताजी सुभाषचंद्र, गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर आदि का नाम लेते हुए इस गीत के विभाजन को उनकी से हुआ बता रहे हैं। यह एक भ्रमजाल और झूठ का पहाड़ है।

एक बंगाली कहावत है – मायेर स्तबेर अर्धेक ग्रहण, अर्धेक बर्जन, ए कैमन सन्तानेर भक्ति? मातृभूमि के स्तुति गीत को आधा स्वीकारना और आधा त्यागना, यह किस प्रकार की संतान की भक्ति है? भद्र बंगाल की सौ वर्षों की व्यथा, वेदना ही इस लोकोक्ति रूप में प्रकट हुई है। भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम का शायद ही कोई दूसरा गीत वन्दे मातरम् जितना भावात्मक, राजनीतिक और ऐतिहासिक रहा हो। बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जी की यह रचना केवल साहित्य नहीं अपितु वह स्वदेशी आन्दोलन, क्रांतिकारियों और राष्ट्रीय जागरण का उद्घट उद्घोष बनी थी। 15 अगस्त, 2026 को कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में कारित घृणित कृत्य से कांग्रेस का इस्लामिक डीएनए पुनः सिद्ध हो गया है। वंदे मातरम् के इस अपमान के समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दशक भर कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे उपस्थित थे। दुस्साहस और दुर्भाग्य का विषय यह है कि इन तीनों ने ही वंदे मातरम् के अपमान के इस दुष्कृत्य को प्रारंभ किया था। इस दुर्भाग्यजनक घटना के बाद कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं ने देश को स्पष्टीकरण देना प्रारंभ किया कि - सोनिया गांधी ने वंदे मातरम् का अपमान नहीं किया बल्कि वे बुजुर्ग खड़गे जी को खड़े होने के कारण असहज होता देखकर उनके लिए कुर्सी मंगा रही थी। यहीं से कांग्रेस नेतृत्व की मूढ़ता, राष्ट्र अनास्था व मुस्लिम तुष्टिकरण के पक्ष में दुराग्रह रखने के चरित्र की पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है। इस घटनाक्रम के अंतरतत्व को समझिए। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को अपने नेतृत्व द्वारा 'वंदे मातरम्' का यह अपमान बुरा लगा इसलिए ही उन्होंने बिना केंद्र या प्रदेश नेतृत्व के कहे ही इस घटना पर कांग्रेस नेतृत्व का बचाव प्रारंभ कर दिया था। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट डाली और कांग्रेस नेतृत्व का बचाव किया। यह 'वंदे मातरम्'

और 'मुस्लिम तुष्टिकरण की कांग्रेसी प्रवृत्ति' के विरोध का प्रतीक था। इस मनोभाव को कांग्रेस के इटालियन नेतृत्व ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। कांग्रेस ने इस घटना पर अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं होती। कांग्रेस ने तो अपनी हठधर्मिता, अड़ियलपन, मति मूढ़ता की हद तो तब दिखा दी जब उसने अपनी राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी में 'वंदे मातरम्' को पूर्ण रूप में नहीं गाने के लिए प्रस्ताव ही पारित कर दिया। 'वंदे मातरम्' के हाल ही में किए गए अपराध और अपमान के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता और आधिकारिक व्यक्तव्य जो कह रहे हैं उसमें वे गांधी जी, नेताजी सुभाषचंद्र, गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर आदि का नाम लेते हुए इस गीत के विभाजन को उनकी से हुआ बता रहे हैं। यह एक भ्रमजाल और झूठ का पहाड़ है। गांधी जी तो इस बात के पक्षधर थे कि यह गीत संपूर्ण देश को जोड़ने वाला प्राणतत्त्व है और इसे इसके पूर्ण वैभव के साथ संपूर्णतः स्वीकार किया जाना चाहिए। गांधी जी ने इसके समर्थन में अपनी स्पष्ट राय रखी थी, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने तुष्टिकरण की अपनी राजनैतिक कुटिलताओं और प्राथमिकताओं के चलते गांधी जी की एक न चलने दी। इतिहास यह भी है कि, यह दुखद एतिहासिक पृष्ठ रहस्यमयी भी है। रहस्य यह कि - अंततः वह कौन सी कमजोर नस थी,, जिसके आधार पर नेहरू जी ऐसे निर्णय भी गांधी जी से करवा लेते थे जिनके लिए गांधी जी कभी भी तैयार नहीं थे। गांधी जी वंदेमातरम् विभाजन हेतु असहमत थे। गांधी जी बंग-भंग हेतु भी सहमत नहीं थे। गांधी जी ने कहा था कि इस देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। गांधी जी स्वतंत्रता पश्चात् कांग्रेस को विसर्जित करने हेतु भी संकल्पित थे। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता पश्चात् हम एक बूँद की स्याही लेंगे और यह लिख देंगे - इस देश में गौहत्या वैसा ही दंड होगा जैसा मानव हत्या के लिए होता है। स्वच्छता, हिंदी राष्ट्रभाषा, ग्रामवासी भारत आदि हेतु भी गांधी जी प्रतिबद्ध थे। कांग्रेस ने सात दशकों की सत्ता में इन विषयों को त्याज्य रखा। 'भारत में रामराज स्थापना' को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया था किंतु 'नेहरू-गांधी कांग्रेस' मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए श्रीराम को ही कल्पना सिद्ध करने के प्रयास में लग गई। कांग्रेस स्वयं को सेकुलर सिद्ध करने के अनथक प्रयास करने लगी थी और 'रामेश्वरम् रामसेतु' के विध्वंस, विनाश, भंजन, खंडन हेतु मशीनें समुद्रतट पर भेज चुकी थी। 'मुस्लिम तुष्टिकरण' हेतु कांग्रेस ने न जाने कितने ही कांड इस देश में किया और सतत-निरंतर किए हैं। आश्चर्य और दुस्साहस का विषय यह है कि 'मुस्लिम तुष्टिकरण' के लिए देश भर से लताड़े जाने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व इस बात को समझ ही नहीं रहा है। हाँ, कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता इस बात कोई समझ भी रहा है और वह कांग्रेस की 'मुस्लिम तुष्टिकरण' की नीति के विरोध में भी है, तब ही तो 'कार्यकर्ता बेचारे' ने सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में आकर यह कहा था कि सोनिया जी वंदे मातरम् का गान रोक नहीं रही थी बल्कि खड़गे जी के लिए कुर्सी बुला रही थी। 'वंदे मातरम्' और 'मुस्लिम तुष्टिकरण' की यह कांग्रेस कार्यकर्ता की नैसर्गिक प्रतिक्रिया थी जिसे कांग्रेस नेतृत्व ने स्वीकार करना चाहिए थे किंतु कांग्रेस ने 'राम पथ' को नहीं बल्कि 'रोम पथ' को चुना हुआ है। 26 अक्टू.- 1 नव. 1937 की कलकत्ता कांग्रेस कार्यसमिति में 'वंदे मातरम्' गान के विभाजन की अनुशंसा और कुछ नहीं बल्कि एक 'इमोशनल राष्ट्रीय ब्लैक मेल' था। यह देश विभाजन में अपना हित देखने वाले नेताओं द्वारा निर्मित 'ब्लैकमेल' था।

क्या चुकंदर खाने से बीपी कंट्रोल होता है?

चुकंदर एक बेहतरीन खाद्य पदार्थ है,अक्सर हम इसे सलाद के तौर पर खाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इससे बीपी भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है?

हाई ब्लड प्रेशर एक आम सी स्वास्थ्य समस्या है लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो इससे आपको गंभीर नुकसान हो सकता है दरअसल उच्च रक्तचाप दिल से जुड़ी बीमारियों का एक प्रमुख जोखिम कारक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इसे कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन की जरूरत होती है हालांकि बीपी को नेचुरल तौर पर कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का अक्सर नाम लिया जाता। इन खाद्य पदार्थों में से एक है चुकंदर। आइए जानते हैं क्या चुकंदर का जूस पीने से या इसे साबुत खाने से बीपी कंट्रोल होता है या नहीं?

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के एक स्टडी के मुताबिक उच्च रक्तचाप के जो मरीज रोज 250 पर लीटर चुकंदर का जूस पीते थे उनके रक्तचाप के स्तर सामान्य सीमा में आ गए। दरअसल चुकंदर में एक प्रकार का रासायनिक तत्व होता है जिसे नाइट्रेट कहते हैं। यह नाइट्रेट रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकते हैं। नाइट्रेट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने में मदद करता है। इससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और रक्तचाप में कमी आती है। यह सूजन को भी काम करने में मदद करता है।

इस रिसर्च में बताया गया है कि नाइट्रेट का सेवन रक्तचाप को कम करने में प्रभावी साबित हो सकता है और सबसे अच्छी बात यह है कि नाइट्रेट हम चुकंदर के साथ और भी हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि या किसी चिकित्सा इलाज का विकल्प नहीं हो सकता है,अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी की परेशानी है तो हमेशा इलाज और दवाओं के लिए अपने डॉक्टर से चर्चा करें।

प्रेग्नेंसी में हम अपना बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस दौरान कहीं गलती से भी अगर कोई केमिकल आपके शरीर में आ जाता है, तो वह कितना नुकसानदायक हो सकता है इसके बारे में आपको पता होगा।

प्रेग्नेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को ना जाने कितनी हिदायत मिलती हैं। प्रेग्नेंसी वैसे तो किसी भी महिला के जीवन का एक अलग अनुभव होता है, पर इस दौरान कई सारी समस्याएं भी उन्हें घेर लेती हैं। उन्हें हर चीज के लिए परफेक्ट होना चाहिए। प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं की स्किन पर भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसे में मन करता है कि तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए जाएं। प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को जिन चीजों से बचना होता है उनमें से एक केमिकल्स भी हैं। अलग-अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहे जो भी दावा करते हों, लेकिन इनमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं।

रेटिनॉल्स को करें अवॉइड

डॉक्टर दिव्या के मुताबिक, रेटिन-ए या रेटिनॉल में विटामिन ए होता है। विटामिन-ए शिशु के विकास के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा से बेबी का सिर, दिल, दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनने में तकलीफ हो सकती है। कुछ एक्ने मेडिसिन भी होती हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। बेहतर है कि इसमें से कुछ यूज करने से पहले आप डॉक्टर से संपर्क कर लें।

सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइल पेरोक्साइड को करें अवॉइड

डॉक्टर का मानना है कि इसके हाई डोज जन्म संबंधित विकार दे सकता है। इससे हार्मोन्स में गड़बड़ी भी हो सकती है। इसके अलावा, एंड्रोजेन प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है जिससे प्रेग्नेंसी के दौरान एक्ने हो सकते हैं।

स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स को करें अवॉइड

कई बार प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को पिगमेंटेशन या मेलास्मा जैसी समस्याएं महसूस होती हैं। हालांकि, यह समय के साथ-साथ चली जाती हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज कर लेती हैं। यह सही नहीं होते। इसमें हाइड्रोक्विनोन जैसे केमिकल्स होते हैं जिससे थोड़ी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं।

केमिकल सनस्क्रीन को करें अवॉइड

सनस्क्रीन लगाना वैसे तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को केमिकल वाली सनस्क्रीन से दूर रहना चाहिए। केमिकल सनस्क्रीन में मौजूद ऑक्सीबेन्जोन और आवोबेन्जोन हार्मोन्स को लेकर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आप नेचुरल और मिनरल सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिनमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे इंग्रीडिएंट्स हों।

बहुत ज्यादा खुशबू वाले प्रोडक्ट्स को करें अवॉइड भले ही वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो या एसेंशियल ऑयल प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ज्यादा खुशबू वाले प्रोडक्ट्स सही नहीं हैं। कई तरह की खुशबू महिलाओं के लिए कॉन्ट्रैक्शंस और माइग्रेन का कारण बन सकती हैं।

यह हर महिला के लिए अलग अनुभव हो सकता है। कुछ को खुशबू अच्छी लग सकती है और कुछ के लिए यह बहुत परेशानी पैदा कर सकता है।

पैथालेट्स को करें अवॉइड

आप ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें पैथालेट्स इंग्रीडिएंट्स हों उन्हें अवॉइड करें। डॉक्टर के मुताबिक, इनमें एंडोक्राइन समस्याएं पैदा करने की शक्ति होती है जिससे ना सिर्फ मां, बल्कि शिशु को भी खतरा हो सकता है।

किन प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं यूज?

- डॉक्टर के मुताबिक, लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड से भरपूर प्रोडक्ट्स को यूज किया जा सकता है।
- इसके साथ, आप विटामिन-सी और नियासिनामाइड को भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
- हयालूरोनिक एसिड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यह स्किन को हाइड्रेशन देगा।
- एलोवेरा स्किन के लिए अच्छा होगा।
- महिलाएं नारियल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।
- फेस वॉश के तौर पर साधारण क्लींजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- आप सेरामाइड से भरपूर मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।
- प्रेग्नेंसी के दौरान कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा नहीं इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।

थायराइड को मैनेज कर सकते हैं ये न्यूट्रिएंट्स

थायराइड को मैनेज करने में हेल्दी डाइट की अहम भूमिका है। थायराइड हार्मोन शरीर के कई फंक्शन्स के लिए जरूरी है। इसका लेवल कम या ज्यादा होने पर सेहत पर इसका असर होता है।

हम सभी सेहतमंद रहना चाहते हैं। हेल्दी रहने के लिए, शरीर में कई विटामिन्स, मिनरल्स और हार्मोन्स का लेवल सही होना जरूरी है। शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने पर या हार्मोनल उतार-चढ़ाव होने पर इसका असर हमारी सेहत पर होता है। थायराइड ग्लैंड से जब थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, तो इसके लक्षण साफ नजर आने लगते हैं। आज के समय में गलत खान-पान और अनियमित जीवनशैली के चलते, थायराइड की दिक्कत बढ़ती जा रही है। खासकर, महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है। थायराइड को मैनेज करने के लिए,डाइट में कई न्यूट्रिएंट्स का शामिल होना जरूरी है। यहां हम आपको कुछ ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहे हैं। इन्हें डाइट में शामिल करने से थायराइड को मैनेज करने में मदद मिलेगी।

थायराइड हार्मोन को मैनेज करने के लिए, आयरन बहुत जरूरी है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है, तो थायराइड ग्रंथि की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। डाइट में आयरन रिच फूड्स को शामिल करें। कैल्शियम भी थायराइड के लिए एक जरूरी मिनरल है। इसकी कमी से भी थायराइड की दिक्कत हो सकती है। वहीं, अगर आपको थायराइड है, तो उसे मैनेज करने के लिए भी कैल्शियम लेवल का सही होना जरूरी है।

विटामिन-सी शरीर के लिए एक जरूरी न्यूट्रिएंट है। यह इम्यूनिटी को मजबूत करता है। विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट थायरॉयड ग्लैंड को सही तरह से फंक्शन करने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम, थायराइड ग्लैंड को सही मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने में मदद करता है। यह मूड को सुधारने और स्ट्रेस को कम करने में भी सहायक है।

सेलेनियम, T4 को सक्रिय करने में सहायता करता है। यह थायराइड लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है।

जिंक की कमी, थायराइड ग्रंथि के सही से काम न करने का कारण बन सकती है। इसलिए, डाइट में जिंक से भरपूर चीजों को शामिल करें।

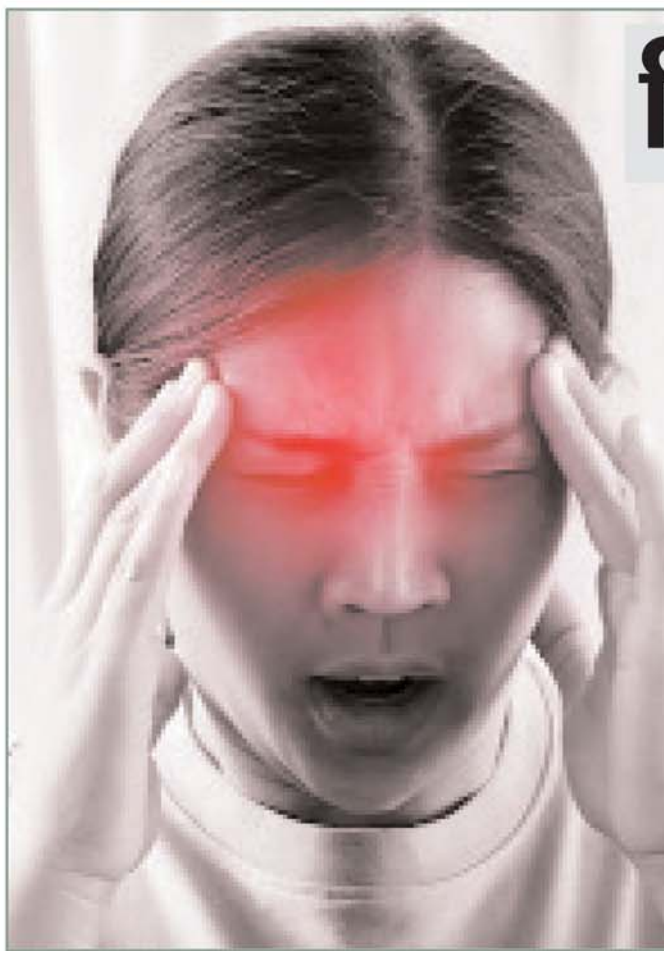

सिरदर्द से परेशान हैं तो पिएं ये आयुर्वेदिक चाय

दिन भर की थकान को खत्म करना हो या फिर सुबह-सुबह उठकर काम पर जाने से पहले होने वाला सिरदर्द, हमेशा दवा लेना सही ऑप्शन नहीं है। कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि सिरदर्द हो क्यों रहा है और हम बिना सोचे-समझे कोई ऐसा उपाय कर लेते हैं जिससे समस्या और बढ़ जाती है। अगर सिरदर्द बार-बार होता है और आपके लिए यह क्रॉनिक हो गया है, तो बेहतर है कि सिरदर्द को खत्म करने का कोई तरीका अपनाया जाए। आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक, हाई ब्लड प्रेशर, हैंगओवर, बुखार, समय पर चाय ना मिलना, स्ट्रेस बढ़ना, मौसम के कारण सिरदर्द होना, इन्सोम्निया, माइग्रेन आदि के कारण हमेशा सिरदर्द बढ़ जाता है। ऐसे में बेहतर है कि आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाए जाएं। कई बार लोग कैफीन एडिक्शन के कारण भी सिरदर्द का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके मरीजों को एक स्पेशल आयुर्वेदिक चाय से बहुत राहत मिली है।

किन चीजों के लिए मददगार है यह चाय?

डॉक्टर दीक्षा के मुताबिक, अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, हैंगओवर है, डायबिटीज की समस्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, ब्लोटिंग से परेशान है, फूड क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस चाय का असर काफी ज्यादा होगा। यह धीरे-धीरे आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाएगी।

कैसे बनानी है यह आयुर्वेदिक चाय?

सामग्री - ◗ 1 ग्लास पानी ◗ 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन ◗ 1 क्रश की हुई हरी इलायची ◗ 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज ◗ 5 पुदीने की पत्तियां

इसे तीन मिनट के लिए आप उबालें और उसके बाद छानकर सिप-सिप कर पिएं। इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं पीना है आप गुनगुनी चाय पी सकती हैं। इससे सिरदर्द की समस्या में बहुत राहत मिलेगी।

कौन सा इंग्रीडिएंट करेगा किस समस्या में मदद?

अजवाइन - यह ब्लोटिंग, अपच, कफ, सर्दी, डायबिटीज और अस्थमा के लिए मददगार साबित हो सकती है।

धनिया के बीज - यह मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसी के साथ, माइग्रेन और अन्य तरह के क्रॉनिक पेन की समस्याओं को यह खत्म कर सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस और थायराइड को ठीक करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है।

पुदीने की पत्तियां - अगर आपको चाय का एडिक्शन है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, इन्सोम्निया की समस्या है, एसिडिटी है, माइग्रेन है, कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, तो पुदीने की पत्तियां मददगार साबित हो सकती हैं।

इलायची - यह मोशन सिकनेस, जी मिचलाने की समस्या, माइग्रेन और ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोगों के लिए अच्छी साबित होती है। यह स्किन और बालों के लिए भी अच्छी है।

आम चाय की जगह आप सुबह उठकर इस चाय को पी सकती हैं। अगर दिन में कभी सिरदर्द हो रहा है, तो भी इसे चुनें।

डाइट में कोई भी मुख्य बदलाव करने से पहले आपको हमेशा डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, तो आप पहले डॉक्टर के पास जाएं और अपनी हेल्थ हिस्ट्री शेयर करें। हो सकता है कि कोई एक चीज किसी को सूट कर जाए और दूसरे इंसान के लिए वो नुकसानदेह हो जाए।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका के अलास्का में चार्टर विमान हुआ क्रैश, दो पायलटों समेत आठ की मौत

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के अलास्का में हुए एक बड़े विमान हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी अलास्का में चार्टर विमान क्रैश

हो गया और उसमें सवार दो पायलटों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई। अमेरिका की सेना ने सभी आठों लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। एक संघीय अधिकारी ने बताया कि विमान उड़ान भरने के बाद पश्चिमी अलास्का के रिमोट इलाके में रडार से गायब हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि चार्टर विमान ने एंकरेज इलाके से उड़ान भरी थी और गुरुवार दोपहर में वह केप न्यूनहैम इलाके में रडार से गायब हो गया। इसके बाद राहत और बचाव दल विमान की तलाश में जुटा। अब अमेरिकी सेना ने विमान के क्रैश होने की पुष्टि कर दी है और बताया कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर की है।

टेक दिग्गज अपने बच्चों को सोशल मीडिया से रखते हैं दूर

वाशिंगटन, एजेंसी। सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान और तेज बनाया है। लेकिन इस तकनीक की दुनिया के बड़े नाम अपने बच्चों के मामले में इसके इस्तेमाल को सीमित रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन लोगों ने डिजिटल दुनिया को इतना बड़ा बनाया, वे अपने बच्चों को इससे क्यों दूर रखना चाहते हैं क्या सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार को प्रभावित कर रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े क्या कहते हैं दुनिया के कई देश बच्चों के लिए सोशल मीडिया की उम्र सीमा तय करने की ओर क्यों बढ़ रहे हैं इन प्लेटफॉर्मस पर कब-कब ऐसे मामले देखने को मिले हैं भारत इस दिशा में क्या कर रहा है मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे लंबे समय तक टीवी या कंप्यूटर के सामने बैठे रहें। उनके अनुसार लोगों के साथ बातचीत करना अच्छी बात है, लेकिन लगातार एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर जाना उतना सकारात्मक नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक मोबाइल फोन नहीं दिया। गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई ने बताया था कि उनका 11 साल का बेटा भी फोन इस्तेमाल नहीं करता था। एप्पल के प्रमुख टिम कुक ने कहा था कि वह अपने भतीजे को सोशल नेटवर्क से दूर रखते हैं। स्नैप के प्रमुख

इवान स्पीगल ने भी अपने बच्चों के स्क्रीन इस्तेमाल को सीमित रखने की बात कही थी। 2018 में उन्होंने अपने सात साल के बच्चे के लिए सप्ताह में केवल 90 मिनट स्क्रीन समय की बात कही थी। बाद में उन्होंने बताया कि उनके दो साल के बच्चे का स्क्रीन समय लगभग शून्य था और छह-सात साल के बच्चे कभी-कभार फिल्म देखते थे, लेकिन फोन इस्तेमाल नहीं करते थे। बच्चों के लिए चिंता केवल इस बात की नहीं है कि वे कितने घंटे स्क्रीन देखते हैं, बल्कि यह भी है कि वे स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं और उसका उनके व्यवहार पर क्या असर पड़ रहा है। यूट्यूब के सह-संस्थापक स्टीव चेन ने छोटे वीडियो को लेकर चिंता जताई थी। उनका डर था कि लगातार छोटे-छोटे वीडियो देखने से बच्चों की लंबी सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं की मई में जारी रिपोर्ट में भी छोटे बच्चों के लिए डिजिटल स्क्रीन को लेकर चिंता जताई गई। रिपोर्ट के अनुसार शिशुओं के लिए डिजिटल स्क्रीन के लाभ सीमित हैं, जबकि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर संभावित जोखिम ज्यादा हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप क्षेत्रीय कार्यालय के अध्ययन में 2022 में 44 देशों और क्षेत्रों के करीब 2 लाख 80 हजार बच्चों को शामिल किया गया। इनमें 11, 13 और 15 साल के बच्चे थे।

दो हफ्ते में परमाणु बम बना लेता ईरान

ट्रंप का तेहरान हमलों पर बड़ा दावा, होर्मुज पर कब्जे को लेकर क्या कहा

वॉशिंगट, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े रणनीतिक जलमार्गों पर लगभग नियंत्रण कर रहा है और जल्द ही वहां पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ट्रंप ने कहा, जब हमने बी-2 बमवर्षकों से उन पर हमला किया, तब वे परमाणु हथियार हासिल करने से ठीक दो सप्ताह दूर थे। यही वजह थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा। ट्रंप ने अपने पूर्व निजी वकील माइकल कोहेन के साथ एक साक्षात्कार में ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने यह भी माना कि इस संघर्ष के कारण अमेरिकी लोगों को पेट्रोल और ऊर्जा की अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

77 डब्ल्यूएबीसी रेडियो पर प्रसारित साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, अब ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। हम जलडमरूमध्य पर नियंत्रण कर रहे हैं और जल्द ही पूरा नियंत्रण कर लेंगे। हम ईरान के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। बुधवार को जारी साक्षात्कार के इस हिस्से में ट्रंप ने जलमार्गों का नाम नहीं बताया। उन्होंने

कहा कि ईरान की नौसेना, वायुसेना और नेतृत्व को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिससे बातचीत के जरिए समझौता करना मुश्किल हो गया है। ट्रंप ने कहा, समस्या का एक हिस्सा यह है कि बहुत से नेता चले गए हैं। समझौता करना आसान नहीं है। कोई नहीं जानता कि नेतृत्व कौन कर रहा है।

उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिकी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने कहा, और मैं उनसे कहता हूं कि आपकी ऊर्जा की लागत थोड़ी अधिक होगी, पेट्रोल की कीमत भी थोड़ी अधिक होगी। लेकिन हमें मध्य पूर्व का सफर तय करना होगा, क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकते।

उन्होंने दावा किया कि ईरान को सैन्य रूप से पूरी तरह तबाह कर दिया गया है और उसकी मिसाइलों तथा ड्रोन बनाने की क्षमता काफी कम हो गई है। उन्होंने बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्यकर्मियों को वेतन नहीं मिलने का भी जिक्र किया और इन्हें तेहरान पर बढ़ते दबाव का संकेत बताया।

उन्होंने कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं इसे फिर से सौ बार करता, वे परमाणु हथियार नहीं रख सकते और उनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों के खिलाफ बी-2 बमवर्षक विमानों के इस्तेमाल का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान देर रात चलाया गया और हर बम अपने लक्ष्य पर गिरा। उन्होंने कहा, जब हमने बी-2 बमवर्षकों से उन पर हमला किया, तब वे परमाणु हथियार हासिल करने से ठीक दो सप्ताह दूर थे। और यही वजह थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि आप उन्हें इस तरह का हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता तो वह इस्राइल और मध्य पूर्व के अन्य देशों पर हमला करता। उन्होंने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन का नाम लेते हुए कहा कि इन देशों को ईरान की मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो इस्राइल नहीं होता। मेरा मानना है कि पूरा मध्य पूर्व तबाह हो जाता, लेकिन इस्राइल निश्चित रूप से तबाह हो जाता। कोहेन कई वर्षों तक ट्रंप के निजी वकील और करीबी सहयोगी रहे।

47 परिवारों को 500 करोड़ रुपये देगा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, मुर्दाघर प्रबंधक ने बेच दिए थे शवों के अंग

बोस्टन, एजेंसी। अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने उन परिवारों को 5.3 करोड़ डॉलर (करीब 500 करोड़ रुपये) देने पर सहमति जताई है, जिनके परिजनों के शवों के अंग चोरी कर काले बाजार में बेचे गए थे। यह मामला स्कूल के पूर्व मुर्दाघर प्रबंधक सेड्रिक लॉज से जुड़ा है। अदालत की मंजूरी मिलने के बाद दो अलग-अलग सामूहिक मुकदमों के निपटारे के लिए यह रकम दी जाएगी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन जॉर्ज क्यू. डेली और बर्नार्ड एस. चांग ने एक पत्र में लॉज की करतूत को बेहद घृणित और मेडिकल समुदाय के मूल्यों के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई।

47 परिवारों ने किया था मुकदमा

इस मामले में उन 47 लोगों के परिजनों ने मुकदमा दायर किया, जिन्होंने मेडिकल रिसर्च और पढ़ाई के लिए अपने शरीर दान किए थे। हार्वर्ड का कहना है कि वह यह निश्चित तौर पर नहीं बता सकता कि लॉज ने किन-किन दानदाताओं के शवों से अंग निकाले थे। स्कूल ने 2018 से मार्च 2023 के बीच दान किए गए शवों के रिकॉर्ड और संघीय जांच से मिली जानकारी की समीक्षा की। इसी आधार पर संभावित रूप से प्रभावित दानदाताओं की पहचान करने की कोशिश की गई।

पत्नी समेत कई लोग दोषी

सेड्रिक लॉज को पिछले साल आठ साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उसकी पत्नी डेनिस लॉज को भी इस मामले में मदद करने के लिए एक साल से कुछ अधिक समय की जेल हुई। इसके अलावा लॉज से शवों के अंग खरीदने वाले छह अन्य लोगों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया और उन्हें सजा सुनाई गई।

दिमाग से लेकर हाथ और चेहरे तक बेचे

लॉज को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, वह शवों के अंग चोरी कर उन्हें दूसरे राज्यों में खरीदारों तक पहुंचाने वाले एक भयावह नेटवर्क के केंद्र में था। उसने शवों से दिमाग, त्वचा, हाथ और चेहरे तक निकालकर बेच दिए। एक मामले में उसने एक खरीदार को मानव त्वचा दी थी, जिसका इस्तेमाल चमड़ा बनाकर एक किताब की जिल्द तैयार करने में किया जाना था। अभियोजक ने इसे बेहद भयावह घटना बताया था। लॉज ने अदालत में स्वीकार किया था कि वह शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेजे जाने से पहले उनके अंग निकालता था।

परिवारों को भुगतान के अलावा छात्रवृत्ति भी

समझौते के तहत हार्वर्ड प्रभावित परिवारों को भुगतान करने के साथ-साथ एक आधिकारिक बयान भी देगा, जिसमें लॉज के कृत्य की निंदा की जाएगी और मेडिकल स्कूल के शव दान कार्यक्रम में किए गए सुधारों की जानकारी दी जाएगी। हार्वर्ड ने यह भी कहा है कि 2027-28 शैक्षणिक सत्र से मेडिकल छात्रों के लिए हर साल एक वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी। लोगों के सम्मान में होगी, जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा और शोध के लिए अपने शरीर दान किए। हार्वर्ड ने बताया कि 2023 में लॉज की गिरफ्तारी के बाद बाहरी विशेषज्ञों के एक पैनल ने उसके शारीरिक दान कार्यक्रम की समीक्षा की थी।

गुलाम जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है विद्रोह

पाकिस्तान में मुनीर की बढ़ी ताकत, नेशनल असेंबली ने लगाई मुहर

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने गुरुवार को सेना और परमाणु कमान ढांचे से संबंधित दो विधेयक पारित किए। इनका मकसद पिछले साल हुए 27वें संविधान संशोधन के बाद सेना के पदानुक्रम में बदलाव को सुव्यवस्थित करना है।

इस संशोधन के जरिये ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद खत्म करके चीफ आफ डिफेंस फोर्सेज (सीडीएफ) का पद बनाया गया है। सीडीएफ का पद अभी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है।

नए प्रविधानों के तहत मुनीर को व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं। प्रस्तावित कानून से रक्षा बल मुख्यालय की स्थापना का रास्ता साफ होगा, जो सशस्त्र बलों के मुख्यालय के तौर पर काम करेगा। यह मुख्यालय सीडीएफ की कमान में होगा। सीडीएफ राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और सशस्त्र बलों से जुड़े सभी मामलों पर प्रधानमंत्री के मुख्य सैन्य

सलाहकार होंगे। सीडीएफ के पास सशस्त्र बलों का परिचालन कमान और नियंत्रण होगा। वह कमान और नियंत्रण से जुड़े मामलों में संघीय सरकार के प्रति जिम्मेदार होंगे। सीडीएफ के पास सशस्त्र बल कानून के दायरे में आने वाले लोगों को सेवानिवृत्त करने, इस्तीफा स्वीकार या अस्वीकार करने, सेवा से हटाने या सेवा में बनाए रखने, रिटायरमेंट की उम्र या सेवानिवृत्ति की समय-सीमा में छूट देने का अधिकार होगा। इस संशोधन के तहत कमांडर आफ द नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड (सीएनएससी) का पद भी बनाया गया है। पिछले महीने जनरल सैयद आमिर रजा को लेफ्टिनेंट जनरल के पद से पदोन्नत कर पहला सीएनएससी नियुक्त किया गया था। नेशनल असेंबली की मुहर ऐसे समय पर लगी जब पीओके में पाक सरकार के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में पाकिस्तान रक्षा बल अधिनियम, 2026 और संशोधित राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण अधिनियम, 2010 विधेयक पेश किए। निचले सदन की मंजूरी के बाद अब इन्हें सीनेट में पेश किया जाएगा।

4 साल से टोरंटो में खड़ा है रूस का एंटोनोव एएन-124 विमान, कनाडाई कोर्ट ने खारिज की रूसी एयरलाइन की याचिका

ओटावा, एजेंसी। यूक्रेन युद्ध के दौरान कनाडा ने रूस के लिए अपने एयरस्पेस बंद कर दिए थे। जिसके चलते पिछले चार सालों से एक रूसी कार्गो विमान कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो के पियरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है। यह विमान न तो उड़ सकता है और न ही वापस रूस लौट सकता है। क्योंकि कनाडाई फेडरल कोर्ट ने रूसी ऑपरेटर वोल्गा-डनेपर एयरलाइंस की रोक हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अब कनाडा सरकार ने इस विशाल विमान को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विमान पर एयरपोर्ट फीस के रूप में रूस की वोल्गा-डनेपर एयरलाइंस 1 मिलियन डॉलर से अधिक का बकाया भी जमा कर दिया है। ऐसे में अब वोल्गा-डनेपर एयरलाइंस अपना विमान वापस मांग रही है या 100 मिलियन डॉलर का मुआवजा की मांग कर रही है।

कैसे फंसा विमान?

रूसी कार्गो विमान दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक है। यह 27 फरवरी, 2022 को चीन से माल लेकर टोरंटो में उतरा। यह विमान कोविड-19 रैपिड टेस्ट किट्स की एक बड़ी खेप कनाडा लेकर आया था। इसी दौरान रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जिसके बाद अलग-अलग देशों ने रूस और यूक्रेन पर अलग-अलग प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए।

इसी दौरान कनाडा की तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मंत्री ओमर अलघाबरा ने घोषणा की कि रूस के किसी भी विमान को अब कनाडाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू कर दिया था। जिसके चलते चीन से कनाडा आए इस विमान को टोरंटो एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और तब से अब तक ये विमान यहीं खड़ा है।

क्यों उड़ान नहीं भर सकता यह विमान?

यूक्रेन युद्ध के दौरान कनाडा सरकार एक नोटिस टू एयरमेन लागू किया। इस नोटिस के अनुसार, किसी भी रूसी रजिस्टर्ड, स्वामित्व वाले, या रूसी संस्था से जुड़े विमान को कनाडाई क्षेत्र में उड़ान की नहीं दी जाती है।

पोको एम 8एक्स 5जी 7900mAh की बड़ी बैटरी के साथ हुआ लॉन्च

बेंगलुरु: शाओमी इंडिया ने आज पोको M8× 5G लॉन्च करने की घोषणा की है। यह क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 4 जेन 5 मोबाइल प्लेटफॉर्म से लैस भारत का पहला स्मार्टफोन है। 7900mAh की बड़ी बैटरी, शानदार टिकाऊपन, 6.9-इंच का बड़ा 120H5 एडैप्टिव डिस्प्ले और एक खास डिज़ाइन के साथ, पोको M8× 5G यूजर्स की दैनिक जीवनशैली, कार्यप्रणाली और मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक भरोसेमंद स्मार्टफोन अनुभव देता है। पोको M8× 5G को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उपयोगकर्ताओं को बार-बार फोन चार्ज करने की चिंता से राहत मिले। चाहे किसी नए शहर में रास्ता देखना हो, काम का लंबा दिन हो, आते-जाते वीडियो देखना हो, ऑनलाइन क्लास लेना हो या देर रात तक कनेक्टेड रहना हो, यह स्मार्टफोन पूरे दिन आपका साथ निभाने के लिए बनाया गया है। 7900mAh की बड़ी बैटरी, जो कई दिनों तक चले पोको M8× 5G में 7900mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिससे आपको

बार-बार फोन चार्ज करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और आप अपना काम आसानी से कर सकेंगे। जब फोन चार्ज करना हो, तो इसके लिए बॉक्स में ही 45W का फास्ट चार्जर मिलता है, जो फोन को जल्दी चार्ज कर देता है। इसके अलावा, इसमें 22.5W का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी है, जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर अपने किसी अन्य डिवाइस या स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। हर माहौल में इस्तेमाल के लिए मजबूत फोन हमेशा एक जगह नहीं रहता। यह ऑफिस की टेबल, कॉलेज की क्लास, भीड़-भाड़ वाले सफर और यात्राओं में आपके साथ रहता है। पोको M8× 5G को IP64 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी की हल्की छींटों से बचाती है। चाहे सफर के दौरान अचानक हल्की बारिश हो जाए या धूल भरी जगह हो, आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इसे कहीं भी ले जा सकते हैं।

इसकी मजबूती को और बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की सुरक्षा दी गई है, जिससे यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आसानी से खराब नहीं होता। बड़ी और स्मूथ स्क्रीन, आपके हर मनपसंद काम के लिए पोको M8× 5G में 6.9-इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जो 120H5 एडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यह स्क्रीन एंटरटेनमेंट, इंटरनेट चलाने और रोज़मर्रा के कामों के लिए बेहतरीन अनुभव देती है। चाहे लंबे सफर में अपना पसंदीदा शो देखना हो, खाना बनाते समय रेसिपी देखनी हो, वीडियो कॉल सेजुड़ना हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, यह बड़ी स्क्रीन आपको हर काम आसानी से करने की सुविधा देती है।

न्यूयॉर्क कैपिटल-टाइम्स स्क्वायर उड़ाने की थी साजिशः यूएस ने नाकाम किया आईएसआईएस का हमला

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अधिकारियों ने अल्बानी स्थित न्यूयॉर्क कैपिटल पर कथित बम हमले की साजिश को नाकाम करते हुए 35 वर्षीय जेसिका बोवी को गिरफ्तार किया है। संघीय जांच ब्यूरो के अनुसार, वह आईएसआईएस के प्रति समर्थन जता चुकी थी, हमले के लिए सरकारी इमारतों की रेकी कर चुकी थी और विस्फोटक को भोजन पहुंचाने की सेवा के जरिए अंदर पहुंचाने की योजना बना रही थी। अधिकारियों ने बताया कि उसे एक निष्क्रिय विस्फोटक और नकली बंदूक दिए जाने के बाद न्यूयॉर्क कैपिटल के पास गिरफ्तार किया गया। आतंकी संगठन को मदद देने की कोशिश का आरोप

बोवी को गुरुवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद विदेशी आतंकवादी संगठन को मदद पहुंचाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे न्यूयॉर्क की राजधानी अल्बानी की संघीय अदालत में पेश किया गया, जहां एक संघीय मजिस्ट्रेट ने उसे हिरासत में भेज दिया। उसके खिलाफ दायर शिकायत में संघीय जांच ब्यूरो ने कहा है कि करीब पांच साल पहले इस्लाम धर्म अपनाने के बाद बोवी ने कुनिया यानी सम्मानसूचक इस्लामी नाम आयशा सैफ अपना लिया था। सामाजिक माध्यमों पर उसने 2001 में अल-कायदा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 9/11 हमलों के समर्थन में पोस्ट किए थे।

संघीय जांच ब्यूरो के अनुसार, बोवी ने कई अन्य अमेरिका विरोधी टिप्पणियां भी की थीं और आतंकवादी संगठनों के प्रति समर्थन जताया था। एक संघीय जांच ब्यूरो के मुखबिर ने उससे संपर्क किया। अदालत में दाखिल शिकायत के अनुसार, बातचीत के दौरान बोवी ने आतंकवादी हमला करने में रुचि दिखाई। उसने कथित तौर पर मुखबिर से कहा, काफिरों का दिमाग उड़ा देना खूबसूरत है।

आईएसआईएस प्रमुख के प्रति निष्ठा की शपथ का दावा

शिकायत के मुताबिक, अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए बोवी ने विश्वासियों के कमांडर और मुसलमानों के खलीफा, मुजाहिद शेख अबू हाफा अल-हाशिमी अल-कुरैशी के प्रति पारंपरिक इस्लामी निष्ठा की शपथ यानी बयाह पूरी कर ली है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, वह इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन का प्रमुख है। संघीय जांच ब्यूरो की शिकायत के अनुसार,

बोवी ने अल्बानी में कई इमारतों की रेकी की। इनमें गवर्नर का कार्यालय भी शामिल था। बाद में उसने न्यूयॉर्क कैपिटल को निशाना बनाने का फैसला किया, जहां राज्य की विधायिका का कामकाज होता है। मुखबिर ने उसकी मुलाकात दो अन्य मुखबिरों से कराई। इन दोनों ने बोवी के समर्थक होने का दिखावा किया और उसकी योजना में मदद करने की पेशकश की।

जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की योजना

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बोवी ने दोनों से कहा कि वह इमारत को जितना संभव हो सके उतना नष्ट करना और बैठक के दौरान राज्य के सीनेटरों को मारना चाहती है। उसने कहा कि जिस जोखिम का वह सामना कर रही थी, उसके बदले वह केवल एक या दो लोगों को मारना नहीं चाहती, बल्कि इससे कहीं अधिक बड़ा नुकसान करना चाहती है। संघीय जांच ब्यूरो के विशेष एजेंट क्रेग ट्रेमारोली ने पत्रकारों से कहा कि बोवी सिर्फ सांसदों को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वह हमारी सरकार के विनाश की मंशा रखती थी।

टाइम्स स्क्वायर और व्हाइट हाउस भी निशाने पर

अदालत में दाखिल शिकायत के अनुसार, बोवी ने हमले के बाद भाग निकलने और देश से बाहर जाने के लिए विमान पकड़ने की इच्छा जताई थी, हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगी। उसने धमकी दी थी कि वह वापस लौटकर और हमले करेगी। इनमें नए साल की पूर्व संध्या पर टाइम्स स्क्वायर में हमला भी शामिल था। शिकायत के अनुसार, वह व्हाइट हाउस को भी निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन उसका मानना था कि वहां हमला करना अधिक मुश्किल होगा।

हमले की कथित योजना के तहत बोवी ने कहा था कि विस्फोटक को खाने की डिलीवरी के सामान के रूप में अंदर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उसने एक भोजन पहुंचाने वाली सेवा से थैला भी हासिल किया था। संघीय जांच ब्यूरो के मुताबिक, जब उसने वह सामग्री खरीद ली, जिसे मुखबिरों ने बम बनाने के लिए जरूरी बताया था, तो उन्होंने एक नकली विस्फोटक तैयार किया। यह वास्तव में निष्क्रिय था। इसके साथ उन्होंने बुधवार को उसे एक नकली बंदूक भी दी। अगले दिन, गुरुवार को उसे न्यूयॉर्क कैपिटल के पास गिरफ्तार कर लिया गया।

एक महीने में कीमत 55 पार, अक्टूबर में 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य सरकार बोली-

चीनी जमाखोरी से हुई महंगी, इथेनॉल कारण नहीं

नई दिल्ली,एजेंसी।

सरकार ने उन दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि चीनी से एथेनॉल बनाने की वजह से बाजार में इसके दाम बढ़े हैं। खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कम उत्पादन, त्योहारी सीजन की मांग और जमाखोरी की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। चीनी के बढ़ते दाम को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जैसे कदम उठाए गए हैं।

एथेनॉल के लिए चीनी का इस्तेमाल घटा

मंत्रालय ने कहा कि चीनी की बढ़ती कीमतों को एथेनॉल बनाने में इसके इस्तेमाल से जोड़ना पूरी तरह गलत है। पेट्रोल में मिलाने के लिए चीनी से एथेनॉल बनाने का हिस्सा 2022-23 सीजन के 12प्रतिशत से घटकर 2025-26 सीजन में करीब 9प्रतिशत रह गया है। मौजूदा समय में देश के कुल एथेनॉल उत्पादन का लगभग 75प्रतिशत हिस्सा अनाज, खासकर मक्के से आ रहा है।

15 दिन से ज्यादा स्टॉक रखने पर

सरकार ने चीनी व्यापारियों और डीलरों पर स्टॉक रखने की सीमा लागू कर दी है। नए नियमों के तहत महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से अधिक की खपत का स्टॉक जमा करके नहीं रख सकते।

मिलों और किसानों को हुआ फायदा

भारत में हर साल करीब 32-34 मिलियन टन चीनी बनती है और इसकी खबत 28-29 मिलियन टन है। पहले यह एक्स्ट्रा चीनी मिलों में फंसी रहती थी, जिससे उनके पैसे ब्लॉक हो जाते थे और वे गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर पाते थे। अब सरकार इस एक्स्ट्रा चीनी और गन्ने का इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाने वाले इथेनॉल को बनाने में कर रही है। इससे मिलों के पास पैसा आया और किसानों को समय पर भुगतान मिलने लगा। 20 अगस्त 2026 तक इस सीजन का 97प्रतिशत बकाया किसानों को चुकाया जा चुका है।

गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी

त्योहारों पर बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाने और दाम कंट्रोल करने के लिए सरकार ने मिलों को 15 अक्टूबर से ही गन्ने की पेराई शुरू करने की सलाह दी है। वक्त से पहले काम शुरू होने की वजह से अक्टूबर महीने में चीनी का उत्पादन 10 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। आम तौर पर इस महीने सिर्फ 3 से 4 लाख टन चीनी ही बन पाती थी। बाजार में इस एक्स्ट्रा चीनी के आने से त्योहारों के दौरान सप्लाई मजबूत रहेगी, जिससे चीनी की किल्लत नहीं होगी और कीमतें भी काबू में रहेंगी।

सरकार की बची भारी सब्सिडी

मिलों की कमाई बढ़ने से अब उन्हें सरकार से मदद की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि सरकार ने 2014 से 2021 के बीच मिलों को 14,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, लेकिन साल 2021-22 के बाद से सरकार को 1 रुपए की भी नई सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ी है।

चीनी भारत में 7.50 महंगी, ग्लोबल मार्केट में 16प्रतिशत की तेजी

देश के रिटेल बाजार में पिछले एक महीने में चीनी के दाम तेजी से बढ़े हैं। 20 जुलाई को जो चीनी 48.18 प्रति किलो थी, वह 20 अगस्त को बढ़कर 55.70 प्रति किलो पर पहुंच गई। चीनी की यह किल्लत सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है। सरकारी अनुमान के मुताबिक, साल 2026-27 में वैश्विक स्तर पर करीब 33 लाख टन चीनी की कमी हो सकती है। दुनियाभर में सप्लाई कम होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चीनी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। सिर्फ 50 दिन में (30 जून से 20 अगस्त) ग्लोबल मार्केट में चीनी का दाम 474 डॉलर से बढ़कर 552 डॉलर प्रति टन (16प्रतिशत से ज्यादा) पर पहुंच गया है।

आईआईटी हैदराबाद में स्थापित होगा जिंदल स्टील उत्कृष्टता केंद्र

उच्च क्षमता, मूल्यवर्धित और लागत-प्रभावी इस्पात उत्पादों व समाधानों पर केंद्रित होगा

नई दिल्ली। जिंदल स्टील (जेएसपीएल) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैदराबाद ने देश के बुनियादी ढांचे, इंजीनियरिंग और रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नत इस्पात समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। इस महत्वपूर्ण साझेदारी के तहत आईआईटी हैदराबाद परिसर में एक जिंदल स्टील उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य उच्च क्षमता और लागत-दक्षता वाले इस्पात उत्पादों का विकास और प्रचार करना है। यह उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से उच्च क्षमता, मूल्यवर्धित और लागत-प्रभावी इस्पात उत्पादों व समाधानों पर केंद्रित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य डिजाइनरों, सलाहकारों, इंजीनियरों, ईपीसी कंपनियों और उपकरण निर्माताओं के साथ मिलकर उन्नत इस्पात ग्रेड के उपयोग की संभावनाओं को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना है। जिंदल स्टील के एक अ?धिकारी ने बताया कि यह साझेदारी भारत के बुनियादी ढांचे, इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च क्षमता और लागत-प्रभावी इस्पात के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जोर दिया कि आईआईटी हैदराबाद की तकनीकी क्षमता और जिंदल स्टील की विनिर्माण, धातुकर्म तथा इंजीनियरिंग विशेषज्ञता को मिलाकर यह केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत, हल्के, तेज और अधिक दक्ष इस्पात समाधान विकसित करेगा।

8.7 करोड़ युवा न पढ़ाई, न काम, न प्रशिक्षण में, नीति आयोग ने बताया- भारत की युवा शक्ति की चुनौतियां

नई दिल्ली।

नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अनुमानित 8.7 करोड़ भारतीय युवा (15 से 29 आयु वर्ग) न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न काम कर रहे हैं और न ही कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह आंकड़ा रियायती प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और स्थानीय मांग व उभरते क्षेत्रों के अनुरूप कौशल प्रदान करना है। आयोग ने विकसित भारत2047 के लिए कौशल विकास की पुनर्कल्पना नामक अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान प्रस्तुत किया है। यह आंकड़ा 2021 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 78वें दौर के आंकड़ों पर आधारित है। आयोग ने भारत के कार्यबल परिदृश्य और सीखने वालों को पांच खंडों में बांटा है। इनमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक कार्य, शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण से बाहर रह रहे युवा व महिलाएं शामिल हैं।

छात्रों को कौशल विकास में बाधाएं आती हैं

छात्र, विशेषकर कम आय वाले परिवारों से, पहले से ही कॉलेज के खर्चों से बोझ तले दबे हैं। कई मामलों में वे निजी ट्यूशन का भी खर्च उठाते हैं। परिणामस्वरूप, पारंपरिक डिग्री के साथ सशुल्क कौशल विकास में अतिरिक्त निवेश करना अक्सर आर्थिक रूप से अव्यवहारिक होता है। कई छात्र स्नातक होने के बाद परिवारों का समर्थन करने के लिए औपचारिक नौकरी या आय स्रोत चुनते हैं। वे अक्सर कम वेतन वाली स्थिर आय वाली नौकरी भी स्वीकार कर लेते हैं।

नीट युवा कौन हैं और उन्हें चाहिए

नीति आयोग ने नीट युवा को 15 से 29 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है। ये वे युवा हैं जो शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं हैं। इसमें बेरोजगार युवा भी शामिल हैं। नीट युवा आय की कमी और पिछली शिक्षा की डूबी हुई लागत से बाधित होते हैं। उन्हें किफायती या रियायती प्रशिक्षण विकल्पों की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें समर्पित वित्तीय सहायता भी चाहिए जहां बाधाएं सबसे अधिक बाध्यकारी हों।

तनाव के बावजूद भारत पर चीनी मोबाइल ब्रांडों की भारी निर्भरता

नई दिल्ली।

भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद चीनी मोबाइल ब्रांड भारतीय बाजार पर अपनी भारी निर्भरता बनाए हुए हैं। चीन के बाहर भारत उनके लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे प्रमुख ब्रांडों के वैश्विक निर्यात में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने उन्हें यहां स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। रिपोर्ट बताती है कि 2025 में वीवो के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा 34 फीसदी था। यह ब्रांड भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है, जिसने 2026 की दूसरी तिमाही में कुल बाजार का 18 फीसदी हिस्सा हासिल किया। अब वीवो, डिक्सन टेक्नॉलजीज के साथ संयुक्त उपक्रम के जरिये भारत में अपने स्मार्टफोन उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रही है। वीवो जैसी ही कहानी अन्य चीनी ब्रांडों की भी है। 2025 में ओप्पो के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा 23 फीसदी, रियलमी के लिए 35 फीसदी और वनप्लस के लिए 32 फीसदी तक पहुंच गया था। ये चारों ब्रांड (वीवो, ओप्पो, रियलमी और वनप्लस) चीन की दिग्गज कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के स्वामित्व में हैं। मोटोरोला, जिसका नियंत्रण अब चीनी कंपनी लेनोवो के पास है, के लिए भी भारत उसके वैश्विक निर्यात में 20 फीसदी का योगदान देता है और कंपनी भारत में असेंबल किए गए फोन सीधे तौर पर अमेरिका को निर्यात कर रही है। लंदन मुख्यालय वाली स्मार्टफोन निर्माता नथिंग के वैश्विक निर्यात में तो भारत की हिस्सेदारी 71 फीसदी हो गई है।

चीन में ऑटो कंपनियों ने 40 लाख कारें वापस मंगवाई

इसमें टेस्ला की 30 लाख कारें, डोर हैंडल में दिक्कतों के कारण फैसला लिया

बीजिंग।

चीन के रेग्युलेटर ने सेफ्टी चिंताओं को देखते हुए टेस्ला और कई प्रमुख चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को 40 लाख से ज्यादा गाड़ियां वापस मंगाने को कहा है। यह इस साल का सबसे बड़ा ऑटो रिकॉल है, जो मुख्य रूप से गाड़ियों के फ्लश या हिडन छिपे हुए डोर हैंडल में आ रही दिक्कतों से जुड़ा है।

29.8 लाख टेस्ला गाड़ियों में डोर हैंडल की सेफ्टी रिस्क

चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन के मुताबिक, अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला चीन में बनी और इम्पोर्ट की गई लगभग 29.8 लाख ईवी वापस मंगा रही है। इनमें टेस्ला के मॉडल 3, मॉडल वाई, मॉडल एक्स और मॉडल एस जैसे मॉडल शामिल हैं। कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए डोर हैंडल से जुड़ी इस तकनीकी समस्या का सही करेगी, ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में कोई जोखिम न रहे।

फ्लश/हिडन हैंडल

एयरोडायनामिक्स बढ़ाने और कार को प्रीमियम लुक देने के लिए बॉडी के अंदर छिपे रहने वाले हैंडल, जो चाबी या हाथ पास ले जाने पर बाहर निकलते हैं।

दुर्घटना के वक्त अंदर फंस जाते हैं लोग, 2027 से लगेगा बैन

चीन और दुनिया के अन्य हिस्सों में हुए कई ईवी हादसों के बाद रेग्युलेटर ने हिडन डोर हैंडल की जांच सख्त कर दी थी। दुर्घटना के बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होने पर ये डिजिटल डोर हैंडल काम करना बंद कर देते थे, जिससे दरवाजे लॉक हो जाते थे और लोग गाड़ी के अंदर ही फंस जाते थे। चाइनीज रेग्युलेटर ने अपनी वेबसाइट पर जारी नोटिस में कहा है कि गंभीर टक्कर या एक्सीडेंट की स्थिति में अगर कार का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होता है, तो ये हैंडल यात्रियों को तुरंत बाहर निकलने से रोकते हैं और बाहर मौजूद बचाव दल को भी अंदर पहुंचने नहीं देते। चीन सरकार ने ऐलान किया है कि अगले साल से ईवी गाड़ियों में फ्लश/हिडन डोर हैंडल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और 2027 तक यह बैन पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा।

10वां सिम कार्ड 24 अगस्त से नहीं मिलेगा

एक्स्ट्रा नंबर 15 दिन में सस्पेंड हो सकते हैं, जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट में 6 सिम की लिमिट

नई दिल्ली। अगर आपके नाम पर 9 सिम कार्ड एक्टिव हैं तो आपको नया सिम कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों के नाम पर पहले से तय लिमिट यानी 9 मोबाइल कनेक्शन हैं, उन्हें कोई भी नया सिम कार्ड जारी न किया जाए। यह नियम इसी महीने की 24 तारीख से देशभर में लागू हो जाएगा। अगर आप तय सीमा से ज्यादा सिम लेने दुकान पर जाएंगे, तो कंपनियां आपको नया कनेक्शन देने से मना कर देंगी। इसके साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि आपके नाम पर पहले से ही अधिकतम सिम कार्ड चालू हैं, इसलिए नया सिम नहीं दिया जा सकता।

30 नवंबर तक कंपनियों को सिस्टम सुधारने की मोहलत

दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम को इस नए सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह जोड़ने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। तब तक कंपनियों को अपना पूरा प्रोसेस दुरुस्त करना होगा ताकि कोई भी एक्स्ट्रा सिम चालू न हो सके।

डिजिटल सिस्टम से पता चलेगा कितनी सिम एक्टिव

अगर आप सोच रहे हैं कि अलग-अलग कंपनियों (जैसे जियो, एयरटेल या वोडाफोन-आइडिया) से सिम लेकर आप बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने को कहा है। इस पोर्टल पर देश के सभी मोबाइल यूजर का डेटा मौजूद है। नया सिम एक्टिवेट करने से पहले कंपनियां इस पोर्टल पर चेक करेंगी कि आपके नाम पर कुल कितने सिम चल रहे हैं।

पोर्टल पर दिखेगा एक्स्ट्रा सिम वालों का फोटो

नियमों को और सख्त बनाने के लिए सरकार 23 अगस्त से डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर जोड़ रही है। इसके तहत, जिन लोगों ने सिम कार्ड की तय सीमा (9 सिम) को पार कर लिया है, उनकी फोटो इस पोर्टल पर दिखाई देने लगेगी। इससे सिम बेचते समय डीलर तुरंत पहचान जाएंगे कि किस ग्राहक को नया सिम देने से मना करना है।

गलती से भी चालू हुआ नया सिम, तो तुरंत होगा सस्पेंड

कंपनियां जब तक इस नए डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह ठीक नहीं कर लेतीं, तब तक के लिए सरकार ने एक अंतरिम रास्ता निकाला है। अगर इस बीच किसी कंपनी से गलती से भी तय सीमा से ज्यादा (10वां या 11वां) सिम कार्ड चालू हो जाता है, तो नियमों के तहत उस नए नंबर को तुरंत एक दिन के लिए सस्पेंड (बंद) कर दिया जाएगा। यह सस्पेंशन तब तक नहीं हटेगा जब तक एक्स्ट्रा सिम का मामला सुलझ नहीं जाता।

राशन वितरण में आएगा बदलाव डिजिटल रुपया रोकेगा धोखाधड़ी

रियल-टाइम ट्रैकिंग प्रणाली लीकेज और हेराफेरी को काफी हद तक कम करेगी

नई दिल्ली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में धोखाधड़ी और सब्सिडी लीकेज पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की खाद्य सब्सिडी अब सीधे लाभार्थियों के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) आधारित डिजिटल रुपया वॉलेट में हस्तांतरित की जाएगी। यह कदम देशभर में लगभग 78.85 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह वितरित होने वाले 19,000 करोड़ रुपये के खाद्यान्न में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

यह उद्देश्य-आधारित डिजिटल सब्सिडी लाभार्थियों को सूचीबद्ध दुकानदारों से खाद्यान्न खरीदने की सुविधा देगी। वे एक सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य डिजिटल भुगतान तंत्र का उपयोग कर सकेंगे। रियल-टाइम ट्रैकिंग प्रणाली लीकेज और हेराफेरी को काफी हद तक कम करेगी। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता क्यूआर कोड से, जबकि साधारण मोबाइल वाले ओटीपी-आधारित वाउचर से भुगतान कर सकेंगे। अप्रयुक्त कूपन स्वतः सरकारी खाते में लौट जाएंगे, जिससे फर्जी एंट्री की संभावना समाप्त होगी और राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। गुजरात, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में सफल परीक्षण के बाद, इस सीबीडीसी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित सात और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की तैयारी है।

, लाजिस्टिक्स सेमिनार में डेडीकेटेड कॉरिडोर में निवेश पर हुई बात

भारतीय रेलवे में आएगी मालवहन क्रांति

नई दिल्ली।

देश की प्रमुख मालवहन कंपनियों ने भारतीय रेलवे में माल ढुलाई को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड मैनेजमेंट (सीटीआरएएम) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मालवहन संगोष्ठी में यह मांग उठी। कंपनियों ने मौजूदा नीति में माल और पार्सल वैगन निवेश को मंजूरी देने की बात कही। संगोष्ठी का विषय 'सिनर्जी ऑन ट्रैकः ट्रांसफार्मिंग इंडियाज लॉजिस्टिक्स-रेल एक्सप्रेस रिवॉल्यूशन' था। प्रतिनिधियों ने ऐसे समर्पित गलियारों में यह व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया जहां यातायात कम रहता है। इससे माल ढुलाई आसान हो जाएगी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिंकेश रॉय ने कहा कि माल और पार्सल वैगन निवेश योजना से निजी निवेश के जरिये माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इससे मालवहन क्षेत्र को काफी फायदा होगा। उन्होंने कम दूरी के कंटेनर परिवहन में सड़क और रेल के बीच लागत के स्तर पर समानता लाने की जरूरत बताई। साथ ही बंदरगाह शुल्क, रेल मालभाड़ा और अंतिम छोर तक परिवहन की लागत को ध्यान में रखने का सुझाव दिया गया। प्रतिनिधियों ने बताया कि रेलवे के पास ऐसे वैगन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। खाली फ्लैट रैक की अनावश्यक आवाजाही रोकने का भी सुझाव दिया गया।

प्रमुख कंपनियों के सुझाव

कॉनकॉर के अंतरराष्ट्रीय बाजार एवं संचालन के निदेशक विजय कुमार सिंह ने आधुनिक मशीनें और एक साथ अधिक सामान लोड करने तथा उतारने वाली प्रणालियां लाने की बात कही। उन्होंने लौह अयस्क की ढुलाई के लिए नए बीओबीएनएस वैगन खरीदने की अनुमति देने की मांग भी उठाई। टाटा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के प्रभात कुमार, डीपी वर्ल्ड रेल के मुख्य परिचालन अधिकारी महेंद्र बिरहाड़े और डीटीडीसी के मुख्य वित्तीय अधिकारी अनील गंभीर ने भी सुझाव दिए। विश्व बैंक एवं एडीबी सलाहकार सचिन भनुशाली, अमेजन इंडिया के कर्नल वीरेश शर्मा और ब्लू डार्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी विक्रम मंसुखानी ने भी मालवहन संबंधी विचार साझा किए। इन सुझावों का उद्देश्य भारतीय रेलवे की माल ढुलाई दक्षता को बढ़ाना है।

ट्रम्प ने कनाडा पर 50प्रतिशत टैरिफ लगाया

तीन दिन की बातचीत बेनतीजा, पीएम कार्नी बोले- यूएस ने आखिरी समय शर्तें बदली

वॉशिंगटन/ओटावा

अमेरिका और कनाडा के बीच 3 दिन तक चली ट्रेड डील की बातचीत नाकाम रही। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार आधी रात से कनाडा के 20 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए) के सामान पर 50प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया। यह टैरिफ कनाडा के अमेरिका भेजे जाने वाले कुल सामान का करीब 5प्रतिशत है। अमेरिका और कनाडा के अधिकारियों ने वॉशिंगटन डीसी में तीन दिन की बातचीत की थी, लेकिन व्यापार समझौता फाइनल नहीं हो सका। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका जितना टैरिफ लगाएगा, कनाडा भी उतना ही जवाब देगा।

अमेरिका बोला- अच्छा ऑफर दिया था, उन्होंने मौका गंवाया

दोनो देशों के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाने के बाद अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कनाडा ने अमेरिका के साथ पार्टनशिप का बहुत अच्छा मौका गंवा दिया है। यूएसटीआर के मुताबिक, उन्होंने कनाडा को किसी भी बड़े एक्सपोर्टर के मुकाबले सबसे अच्छा ऑफर दिया था। लेकिन कनाडा की नई मांगों और पहले किए गए वादों से पीछे हटने की वजह से यह डील नहीं हो पाई। यूएसटीआर ने आगे कहा कि अगर यह डील होती तो इससे एयरोस्पेस में सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन, गलत ट्रेड प्रैक्टिस से निपटने के लिए जरूरी कदम, खनिजों पर सहयोग, और यूएस-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट बातचीत की घोषणा जैसे नतीजे सामने आते।

कनाडा के अमेरिका पर जवाबी टैरिफ

अमेरिका के नए 50प्रतिशत टैरिफ के बाद कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका के टैरिफ का डॉलर-फॉर-डॉलर जवाब देगा। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका जितने मूल्य के कनाडाई सामान पर टैरिफ लगाएगा, कनाडा भी उतने ही मूल्य के अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका और कनाडा एक-दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल हैं, इसलिए टैरिफ बढ़ने का असर दोनों देशों के कारोबार और सामान की कीमतों पर पड़ सकता है।

अमेरिका ने कनाडा पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया

अमेरिका का कहना है कि कनाडा की कुछ व्यापार नीतियां अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसानदेह हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इनमें ऑटोमोबाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, शराब और लकड़ी का कारोबार प्रमुख हैं। अमेरिका ने पहले नए टैरिफ 20 अगस्त से लगाने का ऐलान किया था। हालांकि, डेडलाइन से ठीक पहले दोनों देशों ने बातचीत शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ लागू करने की समयसीमा 3 दिन बढ़ा दी, ताकि समझौते की कोशिश की जा सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, कई मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ अहम मामलों में दोनों देश एक-दूसरे की शर्तों पर सहमत नहीं हो सके।

सरिया कॉलेज में साइबर जागृति अभियान, विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी से बचने के बताए तरीके

सेल्फी QR Code स्कैन कर सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए 'साइबर जागृति अभियान' चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 21 अगस्त 2026 को शशिधर पंडा शासकीय महाविद्यालय सरिया में थाना सरिया के सहयोग से साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और एनएसएस स्वयंसेवकों को साइबर अपराध से बचाव के जरूरी उपाय बताए गए। कार्यक्रम के दौरान थाना सरिया से पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी के अलग-अलग तरीकों की जानकारी दी। फर्जी कॉल और मैसेज, ओटीपी, बैंकिंग जानकारी, संदिग्ध लिंक, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से सावधान रहने की समझाइश दी गई। विद्यार्थियों से कहा गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, पासवर्ड, बैंक संबंधी जानकारी या निजी जानकारी साझा न करें और किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। पुलिस ने साइबर ठगी होने की स्थिति में बिना देरी किए 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करने की जानकारी भी दी। अधिकारियों ने बताया कि ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने से पैसे को रोकने या वापस कराने की संभावना बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करें और किसी अनजान व्यक्ति के भेजे लिंक, फाइल या मैसेज पर भरोसा न करें।यह अभियान केवल कॉलेज तक सीमित नहीं है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस द्वारा जिले के अलग-अलग थाना और चौकी क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, गांवों और सार्वजनिक स्थानों पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के मार्गदर्शन में शुरू हुआ 'साइबर जागृति अभियान' 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक सात चरणों में चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य प्रमिला पटेल, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी हर्षा साहू, मनीष खंडेकर, जयश्री गुप्ता सहित महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं और एनएसएस स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस दौरान विद्यार्थियों से 'साइबर जागृति अभियान' के सेल्फी त्तक्र ष्टश्वस्त्रद्ग को स्कैन कर सेल्फी सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील भी की गई, ताकि साइबर सुरक्षा का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय परिवार ने थाना सरिया की टीम का आभार जताया। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की कि ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

लापरवाही की मार: घरघोड़ा में फ्लाई ऐश से भरे जा रहे गड्ढे, बारिश के साथ खेतों में घुल रही राख

रायगढ़/मूक पत्रिका

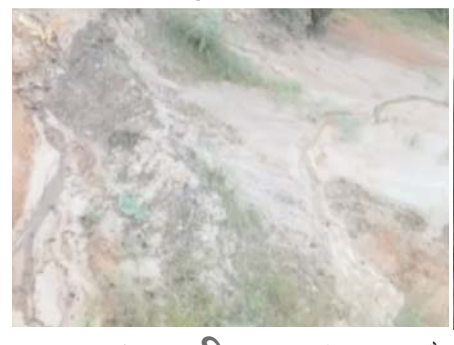

घरघोड़ा बाईपास क्षेत्र में गड्ढों और जमीन को समतल करने के लिए फ्लाई ऐश अनुचित तरीके से डाल जा रहे है।

सामने आई तस्वीरों में सड़क किनारे बड़े पैमाने पर काली-भूरी फ्लाई ऐश जमा दिखाई दे रही है। वहीं, बारिश के बाद फ्लाई ऐश पानी के साथ बहकर आसपास के खेतों और जमीन की ओर फैलती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि फ्लाई ऐश का उपयोग जमीन भराव या समतलीकरण के लिए किया जा रहा है, तो उसे उचित तरीके से ढकने, सीमांकन करने और बारिश के पानी के बहाव को रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कई स्थानों पर राख खुले में पड़ी है, जिससे बारिश के दौरान राख बहकर कृषि भूमि तक पहुंच रही है। फ्लाई ऐश के परिवहन और निपटान को लेकर रायगढ़ जिले में पहले भी सवाल उठते रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक दस्तावेज में रायगढ़ जिले में फ्लाई ऐश के अवैध अपवहन के मामलों में समतलीकरण के बाद मिट्टी की परत बिछाने जैसी कार्रवाई का उल्लेख है। वहीं, वर्ष 2026 में भी रायगढ़-घरघोड़ा क्षेत्र में फ्लाई ऐश के परिवहन और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर रिपोर्टें सामने आई हैं।

अब घरघोड़ा बाईपास की तस्वीरों ने एक बार फिर फ्लाई ऐश के उचित निपटान और पर्यावरणीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि संबंधित विभाग मौके का निरीक्षण कर यह जांच करे कि फ्लाई ऐश किस उद्देश्य से डाली गई है, इसकी अनुमति किस आधार पर है और खेतों में राख के बहाव को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

सावन के अंतिम सोमवार को होगा बाबा गरीबनाथ का सहस्र जलधारा अभिषेक

राजिम । धर्म एवं संस्कृति की पावन नगरी राजिम में सावन मास के अंतिम सोमवार, 24 अगस्त को भगवान शिव के अनन्य भक्तों के लिए भव्य धार्मिक आयोजन किया जाएगा। श्री राजीवलोचन-कुलेश्वरनाथ बोल-बम कांवड़िया संघ के तत्वावधान में रानी श्यामकुमारी धर्मशाला स्थित बाबा गरीबनाथ महादेव मंदिर में बाबा गरीबनाथ का सहस्र जलधारा अभिषेक श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया जाएगा।आयोजन में राजिम सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शिवभक्त एवं श्रद्धालु शामिल होंगे। सुबह 10 बजे महानदी मैया से मानव श्रृंखला बनाकर जल लाया जाएगा। इसके बाद पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा गरीबनाथ महादेव का सहस्र जलधारा से अभिषेक किया जाएगा। सावन के अंतिम सोमवार होने के कारण इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।बाबा गरीबनाथ जी के सहस्र जलधारा अभिषेक कार्यक्रम में राजिम विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रोहित साहू विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उनके शामिल होने से आयोजन को और भव्यता मिलने की उम्मीद है।

प्रशासन को सौंपा ज्ञापन- भव्य आयोजन को देखते हुए संघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गरियाबंद कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित स्थानीय प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा जा चुका है। आयोजन को व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नटवरपुर की छाती पर बीआर रिफाईनरी लगाएगी 150 केएलडी एथेनॉल प्लांट

बेतहाशा पानी की खपत, राउरकेला के कारोबारियों ने रायगढ़ के जंगल में खरीदी जमीन

रायगढ़/मूक पत्रिका

नटवरपुर का जमीन घोटाला सामने आने के पहले वहां का स्वरूप पूरी तरह बदलने की तैयारी की जा रही है। घने जंगलों को काटकर अब दूसरा एथेनॉल प्लांट लगाया जाने वाला है। सरकार ने राउरकेला के कारोबारियों को रायगढ़ की आबोहवा दूषित करने की अनुमति दी है। बीआर रिफाइनरी नामक कंपनी यहां 150 केएलडी क्षमता वाला प्लांट लगाने जा रही है। रायगढ़ शहर के आसपास का पर्यावरण तबाह होने वाला है। स्टील और पावर प्लांटों के बाद अब एथेनॉल प्लांटों के लिए रायगढ़ प्रमुख सेंटर बन रहा है। प्रदेश में अब तक 11 एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है। रायगढ़ जिले में नवदुर्गा फ्यूल्स और मां मंगला इस्पात ने एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। अब राउरकेला के कारोबारियों ने नटवरपुर में 150 किलो लीटर डेली क्षमता का प्लांट लगाने के लिए एमओयू किया है। नटवरपुर में जंगल के बीच करीब 14 एकड़ जमीन खरीदी जा चुकी है। बीआर रिफाइनरी एलएलपी कंपनी का यह प्लांट हजारों टन अनाज और लाखों लीटर पानी की खपत करेगा। प्रदेश का चावल इस प्लांट में खपाया जाएगा। भूजल का अवैध दोहन भी होगा। एथेनॉल प्लांट से होने वाला प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। पेट्रोल से मुनाफा बढ़ाने के लिए कीमती अनाज और पानी इस उद्योग को दिया जाएगा। एक लीटर एथेनॉल के लिए 8-12 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। मतलब रोजाना करीब 15 लाख लीटर पानी उपयोग किया जाएगा जिसकी पूर्ति भूजल दोहन से होगी। चावल, मक्का और गन्ने से ही एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है।

कौन है कंपनी का डायरेक्टर

राउरकेला की कंपनी बीआर रिफाइनरी एलएलपी के डायरेक्टर दिलीप साहू, रोहित अग्रवाल, विवेक खेमका, हर्षवर्धन गर्ग और शशांक गर्ग हैं। कंपनी की नींव 2022 में रखी गई है। सूत्रों के मुताबिक एथेनॉल की डिमांड आते ही कंपनी ने संयंत्र लगाने की योजना बनाई। नटवरपुर में जमीन भी मिल गई है

कोलकाता के मालिकों से खरीदी जमीन

नटवरपुर की जमीनें बेहद आसानी से मिल रही हैं क्योंकि यहां संदेहास्पद रजिस्ट्रियां हुई हैं। बीआर रिफाइनरी के डायरेक्टरों ने खनं 239/1 रकबा 2.6910 हे और 239/2/ख रकबा 2.8330 हे. खरीद ली है। विकास काला, विशाल काला, विनीत काला और संगीता जैन निवासी हावड़ा की जमीन को शशांक गर्ग के नाम पर 2023 में रजिस्ट्री की गई।

सायबर जागृति अभियान के तहत डॉ. खरे ने ग्रामीणों को किया जागरूक

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ÷सायबर जागृति अभियान÷ के तहत थाना सारागांव क्षेत्र में ग्रामीणों को साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. चंद्रशेखर खरे ने ग्रामीणों से साइबर ठगी के प्रति जागरूक और सदैव सतर्क रहने की अपील की। डॉ. खरे ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ह्रञ्जक्क साझा नहीं करना चाहिए, अनजान क्क्य फाइल डाउनलोड या शेयर नहीं करनी चाहिए और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। उन्होंने अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल के प्रति भी सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल 1930 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने ग्रामीणों से ÷मैं जागरूक हूं, साइबर क्राइम से मुक्त हूं÷ का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। यह जागरूकता कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूलैण्डन यार्क के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना सारागांव प्रभारी राकेश सूर्यवंशी, सउनि हीरालाल एक्का, राजेश सिंह, महिला प्रधान आरक्षक श्रीमती सरस्वती जांगड़े, महेश राम केंवर्त्य, श्रीमती हेमलता राठौर, दीपक ठाकुर, दुर्गेश सूर्यवंशी सहित थाना स्टाफएवं ग्रामीण गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कृषक समाज एवं जनजागरूकता के क्षेत्र में निरंतर सक्रियता के लिए ग्रामीणों एवं थाना स्टाफद्वारा डॉ. चंद्रशेखर खरे का श्रीफल भेंटकर सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने साइबर अपराधों से बचने के लिए सतर्क रहने तथा आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। डॉ. खरे ने कहा कि ÷जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज और सुरक्षित देश का निर्माण कर सकते हैं।÷

तकनीक, नवाचार और उन्नत कृषि की ओर साहू समाज का कदम, छत्तीसगढ़ प्रदेश संघ आई.टी. सेल एवं किसान प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक संपन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ को आधुनिक, संगठित और आत्मनिर्भर समाज की दिशा में आगे बढ़ाने की पहल के तहत आई.टी. सेल प्रकोष्ठ एवं किसान प्रकोष्ठ की संयुक्त प्रथम बैठक का आयोजन श्री भामाशाह छात्रावास, साहू कॉम्प्लेक्स, टिकरापारा, रायपुर स्थित प्रदेश साहू संघ कार्यालय में किया गया। बैठक में सामाजिक संगठन को तकनीक, नवाचार, उन्नत कृषि और आधुनिक सोच से जोड़ने को लेकर महत्वपूर्ण एवं सार्थक चर्चा हुई। बैठक में आई. टी. सेल प्रकोष्ठ द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से समाज की गतिविधियों, उपलब्धियों एवं सकारात्मक संदेशों को आधुनिक और प्रभावी तरीके से जन-जन तक पहुंचाने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए नवाचार अपनाने तथा समाज को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। वहीं किसान प्रकोष्ठ द्वारा उन्नत एवं आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर समाज के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्ययोजना पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नवीन दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक कार्यो में सक्रियता, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हुए परिवार संस्कार कार्यशाला की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया तथा पदाधिकारियों से समाज को अधिक सशक्त, संस्कारित, संगठित एवं प्रभावी बनाने के लिए मिलकर कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष साधना साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. तिलक साहू, प्रदेश महामंत्री चित्रलेखा साहू, प्रदेश संयुक्त सचिव प्रदीप साहू, आई.टी. सेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक द्वारिका साहू, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक चोवाराम साहू, सुखुराम साहू, राजेंद्र साहू, माधव साहू ,सेवन साहू, भरत साहू, राम साहू,सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि समाज की प्रगति केवल परंपराओं को सहेजने से नहीं, बल्कि समय के साथ तकनीक, शिक्षा, रोजगार, कृषि और नवाचार को अपनाने से संभव है। आई.टी. सेल और किसान प्रकोष्ठ जैसे विषय-आधारित प्रकोष्ठ समाज की प्रतिभाओं और संसाधनों को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन आई.टी. सेल प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी महामंत्री मनीष कुमार साहू तथा कार्यक्रम का संचालन किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बल्ला साहू ने किया। बैठक के अंत में दोनों प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं एवं सकारात्मक गतिविधियों को पहुंचाने तथा संगठित, संस्कारित, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया।

नारियल लड्डू, पापड़ी व पनीर का लिया सैंपल, साफसफाई को लेकर जारी किया नोटिस

श्याम स्वीट्स, रमेश मद्रासी व दिनशॉ में फुड एवं सेफ्टी की दबिश

रायगढ़/मूक पत्रिका

राखी त्यौहार को लेकर जिले में चलाए जा रहे बने खाबो बने रहिबो अभियान के तहत शुक्रवार को जिले के कई प्रतिष्ठानों में फुड एवं सेफ्टी विभाग ने दबिश दिया जहां गंदगी पाए जाने पर नोटिस दिया तो वहीं कुछ प्रतिष्ठानों से मिठाई व पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है।उल्लेखनीय है कि जिले में चल रहे मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर इन दिनों खाद्य वं औषधि विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, जिसको लेकर लगातार शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में दबिश देकर जांच किया जा रहा है। इससे शुक्रवार को भी टीम शहर में निकली थी, जिससे कई प्रतिष्ठानों की जांच किया। जिसमें कई जगहों पर गंदगी पाए जाने पर प्रतिष्ठान संचालक को नोटिस जारी किया है। इस अभियान के तहत शहर के सिंधी कालोनी स्थित श्याम स्वीट्स में दल ने दबिश दिया, जहां जांच के दौरान गंदगी के बीच खाद्य पदार्थ तैयार करते पाए जाने पर नारियल लड्डु का नमूना लिया गया, साथ ही प्रतिष्ठान संचालक को व्यवस्था में सुधार के लिए 15 दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किया गया है। वहीं निर्धारित समय में सुधार न होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में स्टेडियम के पीठे रमेश मद्रासी के पापड़ी मुर्की बनाने वाले स्थान का भी औचक निरीक्षण किया गया। यहां भी खाद्य सामग्री की लेबलिंग और साफ-सफाई के मानकों में कमी मिली। इस पर पापड़ी का नमूना लिया गया और प्रतिष्ठान को आवश्यक सुधार के लिए नोटिस दिया है। इसके अतिरिक्त, जिंदल हॉस्पिटल के सामने स्थित दिनशॉ का भी निरीक्षण किया गया। जहां संदेह होने पर यहां से पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा है।

सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देश- इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुधा चौधरी ने बताया जांच के साथ सुरक्षा की समझाईश दी जा रही है। ऐसे में प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देशित किया गया है कि खाद्य सामग्री पर सही लेबल लगाए, खाद्य पदार्थों को अखबारी कागज में पैक न करने तथा तेल को दो बार से अधिक गर्म कर उपयोग न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अगर कोई प्रतिष्ठान निर्देश के बाद भी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नशीली व नकली दवा को लेकर चार मेडिकल प्रतिष्ठानों की जांच- नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार नशीली एवं नकली दवाओं के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए रायगढ़ शहर में राज्यव्यापी विशेष सघन प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सीएण्डएफ एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, थोक औषधि विक्रेताओं सहित संदिग्ध प्रतिष्ठानों को चिन्हांकित कर उनके यहां दवाओं के क्रय-विक्रय, स्टॉक एवं संबंधित अभिलेखों की गहन जांच की जा रही है। इसी क्रम में 21 अगस्त को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने रायगढ़ शहर में सुमित फार्मा, श्रीराम मेडिकल स्टोर, ओम मेडिकल स्टोर एवं अनुराग मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठानों में उपलब्ध औषधियों के स्टॉक, क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेजों तथा अभिलेखों की नियमानुसार जांच की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जांच के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में औषधि नियमों का उल्लंघन अथवा अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।